एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

सितम्बर 2015
VOL. XXIX ISSUE III

इस अंक में

4 एक्ज़िम बैंक की प्रशिक्षण कार्यशाला – निर्यात क्षमताएं बढ़ाना
5 चीन के साथ भारत की व्यापार संभाव्यता
6 भारतीय टेक्सटाइल उद्योग: निष्पादन और संभावनाएं
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण व्यवस्थाएं
8 तिमाही एक पुनरावलोकन
9 एक्ज़िम बैंक समाचार
10 भारतीय औषधि उद्योग
11 भारत की विदेश व्यापार नीति 2015-2020
12 एक्ज़िम बैंक की गतिविधियां और साहित्य समीक्षा
13 देश विदेश
14 मुद्रा संचलन
15 एक्ज़िम बैंक ने वर्ष 2014-15 में जोरदार कारोबार वृद्धि दर्ज की
16 भारतीय अर्थव्यवस्था - एक नजर
17 भारत का व्यापार निष्पादन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

हालिया वैश्विक आर्थिक गतिविधियां

अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2015 रिपोर्ट के अनुसार, 2015 की पहली छमाही में वैश्विक वृद्धि में गिरावट आई जो उभरते बाजारों में मंदी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर सुधार दर्शाता है. वृद्धि दर समग्र रूप में 2015 के लिए 3.1 प्रतिशत अनुमानित है जो 2014 की तुलना में 0.3 प्रतिशत बिन्दु कम है (तालिका 1). पिछले वर्ष की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में थोड़ी तेजी आने की उम्मीद है, जबकि उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट का अनुमान है. घटती पण्य कीमतें, उभरते बाजारों की मुद्राओं में मूल्यह्रास और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता भविष्य के लिए विशेषकर उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए गिरावट का जोखिम प्रस्तुत करती है. तथापि आईएमएफ के पूर्वानुमानों के अनुसार, उभरते बाजारों तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं दोनों में जोरदार कार्य-निष्पादन से वैश्विक गतिविधियों के 2016 में कुछ गति पकड़ने की उम्मीद है.

उन्नत अर्थव्यवस्थाएं

आईएमएफ द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 2015 की पहली छमाही के दौरान 2.9 प्रतिशत वैश्विक वृद्धि दर्ज की गई है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 2015 में 2.0 प्रतिशत (2014 में 1.8 प्रतिशत की तुलना में) और 2016-17 में औसत 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है. वृद्धि में प्रत्याशित उछाल यूरो क्षेत्र में सुधार, संयुक्त राज्य में लगातार जोरदार कार्यकलाप और जापान के मौद्रिक, राजकोषीय तथा संरचनात्मक नीतिगत प्रयासों का परिणाम है.

यू एस में दूसरी तिमाही में जोरदार वृद्धि के बावजूद 2015 की पहली छमाही में वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर थी. कठोर शीत ऋतु तथा पोर्ट की बंदी और साथ ही तेल क्षेत्र में कम पूंजी व्यय के कारण पहली तिमाही में कार्यकलापों में कमजोरी रही. तथापि ऊर्जा की गिरती कीमतों, राजकोषीय सुधारों, मजबूत बैलेंस शीट तथा सुधरते आवास बाजार की बदौलत यू एस में समुत्थान (रिकवरी) की गति जारी रहने की उम्मीद है.

कमजोर यूरो मुद्रा तथा तेल की घटती कीमतों और बैंक ऋण आपूर्ति में सुधार की बदौलत यूरो क्षेत्र में रिकवरी 2014 के उत्तरार्द्ध से प्रत्याशित गति से अधिक तेजी से हुई है. जून 2014 से यूरो के मूल्यह्रास का 2015 में यूरो क्षेत्र

तालिका 1: वैश्विक वृद्धि का विवरण (प्रतिशत)

	2013	2014	2015[P]	2016[P]
विश्व उत्पादन	3.3	3.4	3.1	3.6
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.1	1.8	2.0	2.2
संयुक्त राज्य	1.5	2.4	2.6	2.8
यूरो क्षेत्र	-0.3	0.9	1.5	1.6
जर्मनी	0.4	1.6	1.5	1.6
फ्रांस	0.7	0.2	1.2	1.5
इटली	-1.7	-0.4	0.8	1.3
स्पेन	-1.2	1.4	3.1	2.5
जापान	1.6	-0.1	0.6	1.0
यूके	1.7	3.0	2.5	2.2
कनाडा	2.0	2.4	1.0	1.7
उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	5.0	4.6	4.0	4.5
स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल	2.2	1.0	-2.7	0.5
रूस	1.3	0.6	-3.8	-0.6
उभरता और विकासशील एशिया	7.0	6.8	5.5	6.4
चीन	7.7	7.3	6.8	6.3
भारत	6.9	7.3	7.3	7.5
आसियान-5	5.1	4.6	4.6	4.9
उभरता तथा विकासशील यूरोप	2.9	2.8	3.0	3.0
लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई	2.9	1.3	-0.3	0.8
ब्राजील	2.7	0.1	-3.0	-1.0
मेक्सिको	1.4	2.1	2.3	2.8
उप-सहरीय अफ्रीका	5.2	5.0	3.8	4.3
उपभोक्ता मूल्य				
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.4	1.4	0.3	1.2
उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	5.8	5.1	5.6	5.1-

पी – अनुमान - स्रोत : आईएमएफ, डब्ल्यूईओ

की वृद्धि में लगभग ½ प्रतिशत बिन्दु योगदान होने की उम्मीद है, जबकि तेल की कम कीमतों से उपभोक्ता व्यय तथा कॉरपोरेट लाभ को बढ़ावा मिलेगा. सामान्य रूप में, तेल की कम कीमतों, मौद्रिक नरमी और यूरो मूल्यह्रास के चलते यूरो क्षेत्र में सामान्य सुधार के 2015-16 के दौरान जारी रहने का अनुमान है.

जापान में 2014 के उत्तरार्द्ध में आर्थिक कार्यकलापों में उछाल आना शुरू हुआ और 2015 की पहली तिमाही में जोरदार उछाल रहा. विस्तारक नीतियों की बदौलत वृद्धि दर के 2016 में 1.6 प्रतिशत तक बढ़ने से पहले 2015 में औसत 0.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाएं

हालांकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि सामान्य रही किन्तु अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बाह्य दशाओं ने कठिन स्थितियां उत्पन्न कीं. वैश्विक आर्थिक संकट के बाद लगभग 7.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर लेने के बाद 2011 में यह घटकर लगभग 6.3 प्रतिशत तथा 2014 में 4.6 प्रतिशत हो गई. 2015 में इसके और घटकर 4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है.

वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए संरचनात्मक समायोजनों तथा नीतिगत प्रयासों के चलते चीन में वृद्धि दर 2015 में मामूली रूप से घटकर 6.8 प्रतिशत तथा 2016 में 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. 2015 की पहली छमाही के दौरान चीन में निवेश वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में मंद रही और आयात में संकुचन आया, लेकिन उपभोग वृद्धि दर स्थिर बनी रही. रियल एस्टेट, ऋण तथा निवेश में पहले की अधिकता कम हुई निवेश की वृद्धि दर में, विशेषकर आवासीय रियल एस्टेट की वृद्धि दर में और कमी आई है.

तेल की गिरती कीमतों और भौगोलिक-राजनैतिक प्रतिबंधों के साथ 2014 में तीव्र मंदी आई है और इससे 2015 में रूसी परिसंघ में संकुचन आने की संभावना है. निवेशक विश्वास में कमी, नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि और पण्यों की न्यून कीमतों का असर 2015 में ब्राजील में वृद्धि पर पड़ सकता है जिसमें 2016 में मामूली सुधार हो सकता है. इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका में वृद्धि धीरे-धीरे पुन: गति पकड़ रही है लेकिन यह वृद्धि ऊर्जा की कमी, नीतिगत अनिश्चितता के चलते निवेशकों की बेरुखी व मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों में प्रत्याशित कड़ाई से थमती जा रही है. भारत में आर्थिक कार्यकलाप मजबूत विश्वास की बदौलत तेजी पर हैं क्योंकि सरकार अपने सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है तथा तेल की न्यून कीमतें जोखिम पर अंकुश लगाने में सहायक हुई हैं.

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां भी आशा के विपरीत कमजोर हैं जो निर्यात में कमी तथा देशी मांग में मंदी दर्शाता है. मलेशिया और कुछ हद तक इंडोनेशिया में कमजोर व्यापार के चलते इस वर्ष मंदी के व्याप्त होने की संभावना है. दूसरी ओर, थाईलैंड में नीतिगत अनिश्चितता में कमी के फलस्वरूप वृद्धि में तेजी आने का अनुमान है. फिलीपीन्स में वृद्धिदर लगभग 6 प्रतिशत पर मोटे तौर पर स्थिर रहने तथा वियतनाम, जिसे तेल की कीमतों में गिरावट से लाभ हो रहा है, में मजबूत होकर 6.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है.

लैटिन अमेरिका में, पण्य कीमतों में गिरावट के साथ क्षेत्र के अन्य देशों में वृद्धि में कमजोरी की गति बनी रही. मेक्सिको में भी वृद्धि दर अपेक्षा से कमतर थी जो यूएस में धीमी वृद्धि तथा तेल के उत्पादन में गिरावट का द्योतक है. क्षेत्र में 2016 में सामान्य सुधार दर्ज करने से पूर्व 2015 में आर्थिक कार्यकलापों में संकुचन की संभावना है.

मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका (मेना) क्षेत्र में भी आर्थिक कार्यकलाप तेल व पण्यों की कीमतों में गिरावट और कुछ देशों में भौगोलिक-राजनैतिक तथा घरेलू संघर्ष के चलते उम्मीद से कम रहा. क्षेत्रीय संघर्षों के प्रभाव-विस्तार, सुरक्षा चिंताएं और सामाजिक तनाव विकास पर भारी पड़ रहे हैं और उच्चतर वृद्धि को रोक रहे हैं. तेल की गिरती कीमतें भी तेल निर्यातकों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं. तेल की कीमतों में जबर्दस्त गिरावट तेल निर्यातक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है. इनमें से अधिकांश (इराक, लिबिया, यमन) गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे हैं या उनके पास सीमित स्टॉक है (ईरान, ईराक). तेल आयातक देशों के लिए तेल की कम कीमतों के सकारात्मक प्रभाव क्षेत्र के अन्य देशों से न्यून विप्रेषण तथा सुरक्षा जोखिमों के विस्तार द्वारा अंशत: समंजित हो जाते हैं. मेना में वृद्धि दर 2015 में 2.2 प्रतिशत के स्तर पर सपाट रहने की उम्मीद है.

तेल की कम कीमतों ने उप-सहारीय (अंगोला, नाइजीरिया) पण्य निर्यातक देशों में वृद्धि को काफी कम कर दिया है. सस्ते तेल क्षेत्र ने गैर-तेल क्षेत्र में भी कार्यकलापों को मंद कर दिया है. क्षेत्र में वृद्धि दर घटकर 3.8 प्रतिशत हो जाने का पूर्वानुमान है.

2015 की पहली छमाही के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रधान मुद्रास्फीति में गिरावट आयी जो मुख्यत: तेल की कीमतों में गिरावट और अन्य पण्यों की कीमतों में नरमी दर्शाती है, जबकि मूल मुद्रास्फीति स्थिर रही. जहां तक उभरते बाजारों का संबंध है, तेल तथा अन्य पण्यों (खाद्य सहित जिसका उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उपभोक्ता, मूल्य सूचकांक में काफी भार है) की कम कीमतों ने मुद्रा के भारी मूल्यह्रास से जूझ रहे रूस जैसे देशों के सिवाय अन्य देशों में सामान्यत: मुद्रास्फीति की कमी में योगदान दिया है. नियत विनिमय दर के साथ तेल आयातक देशों तथा तेल निर्यातक देशों में प्रधान मुद्रास्फीति सामान्यत: ऊर्जा तथा परिवहन की गिरती कीमतों के चलते कम हुई है, जबकि मूल मुद्रास्फीति मोटे तौर पर स्थिर रही है.

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2015 में मुद्रास्फीति में गिरावट का अनुमान है जो मुख्यत: तेल की कम कीमतों का प्रभाव दर्शाता है. इसी प्रकार, विकासशील तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों में गिरावट तथा कार्यकलाप में मंदी का वर्ष के दौरान न्यून मुद्रास्फीति में योगदान की उम्मीद है.

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

अमेरिका में मौद्रिक दशाओं की प्रत्याशित कड़ाई और साथ ही अन्य प्रमुख केन्द्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक विस्तार ने यूएस डॉलर के मूल्य में वृद्धि में योगदान दिया है और यह विकासशील देशों को पूंजी प्रवाह पर दबाव डाल रहा है. कई विकासशील देशों की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं, विशेषकर उन देशों की मुद्राएं जहां वृद्धि की संभावनाएं कमजोर हैं या जोखिम अधिक हैं. कुछ देशों में इन प्रवृत्तियों ने डॉलर में मूल्यांकित भारी देयताओं के चलते तुलन-पत्र एक्सपोजर के बारे में चिंताएं उत्पन्न

कर दी हैं. कमजोर यूरो तथा येन के कारण (व्यापार-भारित मूल्य की दृष्टि से) मुद्रा मूल्यह्रास थोडा कम रहा है, जो निर्यात बढ़ाने व प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए केवल सामान्य संभावनाएं ही प्रस्तुत कर रहा है.

प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में विनिमय दर घट-बढ़ अगस्त 2014 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान भारी उतार-चढ़ाव भरी रही, हालांकी हाल के महीनों में यह अपेक्षाकृत सामान्य रही है. वास्तविक मूल्य की दृष्टि से यूरो तथा यूएस डॉलर के मूल्य में मार्च तथा अगस्त 2011 के बीच वृद्धि हुई है, जबकि येन थोड़ा कमजोर हुआ है. विनिमय दर अस्थिरता, विशेषकर रेनमिन्बी के मूल्यह्रास के बाद विनिमय दर लोच में घोषित वृद्धि से अगस्त 2015 में बढ़ी है.

विश्व व्यापार

आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक निर्यात 2014 में 18.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहा जो पिछले वर्ष के कुल 18.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. मात्रा की दृष्टि से 2014 में माल के वैश्विक व्यापार में वृद्धि 3.3 प्रतिशत रही (तालिका 2). उन्नत अर्थव्यवस्थों ने 2014 में माल के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. गैर-ईंधन प्राथमिक पण्यों की विश्व व्यापार कीमतें 2013 में 1.2 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 2014 में 4 प्रतिशत गिरीं. तेल की कीमतों में 2014 में 7.5 प्रतिशत की कमी आई, जबकि विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें इसी वर्ष के दौरान 0.6 प्रतिशत बढ़ीं.

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार बढ़ने का पूर्वानुमान है. उभरते बाजारों में आयात वृद्धि में गिरावट का अनुमान है जो कमजोर होती देशी मांग और घटती विनिमय दर दर्शाती है. निर्यात वृद्धि मध्य पूर्व से उच्चतर तेल निर्यात तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देशी मांग में उछाल के फलस्वरूप बढ़ने की उम्मीद है.

निजी पूंजी प्रवाह, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता शेष

उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी पूंजी अंतर्वाह गत वर्ष के 1.273 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 2014 में घटकर 1.032 बिलियन यूएस डॉलर ही रह गया. अधिकांश गिरावट रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण रूस को पूंजी प्रवाह में जबर्दस्त कमी के कारण थी. वृद्धि में निरंतर कमी और विशेषकर फेडरल रिजर्व द्वारा अमेरिकी ब्याज दरों में प्रत्याशित वृद्धि के प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं तथा चीन की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के चलते 2015 की पहली छमाही के दौरान उभरते बाजारों को पूंजी प्रवाह में गिरावट जारी रही. उभरते बाजारों के पूंजी प्रवाह में हालिया गिरावट में पोर्टफोलियो प्रवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है. पोर्टफोलियो ईक्विटी तथा ऋण प्रवाह ने भी स्टॉक मॉर्केट में बिकवाली के संदर्भ में प्रमुख भूमिका निभाई.

उभरती अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2014 में 0.5 प्रतिशत दर्ज किया गया. मध्य पूर्व क्षेत्र का चालू खाता अधिशेष कम हुआ. इसके अलावा, उप-सहारीय अफ्रीका का चालू खाता घाटा (कैड) और बढ़ गया. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाते अधिशेष से 2015 के दौरान 0.1 प्रतिशत के घाटे की पूर्ति होने की उम्मीद है.

तालिका 2 : माल तथा सेवाओं में वैश्विक व्यापार प्रवाह (प्रतिशत परिवर्तन)

	2013	2014	2015[P]	2016[P]
विश्व व्यापार मात्रा	3.3	3.3	3.2	4.1
निर्यात				
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.9	3.4	3.1	3.4
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	4.4	2.9	3.9	4.8
आयात				
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.0	3.4	4.0	4.2
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	5.2	3.6	1.3	4.4

पी – अनुमान - स्रोत : आईएमएफ, डब्ल्यूईओ 2015

वैश्विक पण्य कीमतें

तेल की कीमतें 2014 की दूसरी छमाही में तीव्र गिरावट के बाद कुछ स्थिर होना शुरू हुई हैं किंतु इनके अभी भी 2013 के स्तरों से बहुत नीचे रहने की उम्मीद है. अमेरिकी शेल ऑयल उद्योग में पर्याप्त क्षमता समायोजन के फलस्वरूप कीमतें जनवरी के न्यून स्तर से कुछ बढ़ी हैं. लगातार कमजोर मांग, प्रचुर तथा बढता वैश्विक स्टॉक और संघर्ष-ग्रस्त यमन, इराक तथा लिबिया में अप्रत्याशित रूप से ठोस उत्पादन तेल की कीमतों को 2013 के उच्च स्तरों से नीचे रखने में योगदान दे रहे हैं (आईईए 2015). ईरान के साथ हाल ही में तय अंतर्राष्ट्रीय करार से आपूर्ति और बढ़ने की संभावना है. तेल की कीमतें 2015 में औसत 58 यूएस डॉलर प्रति बैरल और 2018 तक प्रति बैरल 70 यूएस डॉलर से कम रहने की उम्मीद है (वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, विश्व बैंक). अन्य पण्यों की आपूर्ति में वृद्धि तथा सुस्त मांग के साथ तेल की कम कीमतों के दूसरे दौर के प्रभाव से अधिकांश पण्यों की कीमतों के मध्यावधि में निम्न रहने की उम्मीद है.

चीन के घटनाक्रम मूल धातु (बेसीक मेटल) बाजार में अहम भूमिका अदा करते हैं. इन धातुओं की वैश्विक खपत में चीन का हिस्सा 2000 के प्रारंभ में 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है. इसमें से कुछ वृद्धि विनिर्माण केन्द्र के रूप में देश की भूमिका से संबंधित है, लेकिन यह वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009-2013 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश तथा निर्माण में तेजी भी दर्शाता है. मूल धातुओं की कीमतों में गिरावट में चीन की वृद्धि में गिरावट और धीमे निवेश का अहम योगदान रहा है. मांग में वृद्धि अनुमानों के अनुसार अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी. कीमतों के अल्पावधि में मोटे तौर पर एक तरफ रहने की संभावना है.

04 विकासशील एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश

औद्योगिक निवेश के लिए एशिया में बढ़ती भूख, बढ़ती आधारभूत संरचनाएं और व्यापार बढ़ाने की इसकी चाहत ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है. एशिया ने स्वयं को वैश्विक जगत में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है. इस क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी महत्व मिल रहा है. आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्तूबर 2015 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीडीपी में विकासशील एशिया का हिस्सा 2004 के 4 प्रतिशत से दुगुने से अधिक बढ़कर 2014 में 19 प्रतिशत हो गया है और 2020 तक इसके 24 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है. वस्तुत: दो एशियाई देश अर्थात चीन और भारत आज पीपीपी की दृष्टि से विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुके हैं.

विकासशील एशिया – एक मुख्य व्यापार तथा निवेश भागीदार

जहां तक व्यापार का संबंध है, विश्व व्यापार में विकासशील एशिया का हिस्सा 2000 के 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 34.2 प्रतिशत हो गया है, इस प्रकार यह एक अग्रणी व्यापारिक भागीदार बन गया है; जबकि यूरोप तथा अमेरिका में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा विकसित यूरोप के लिए 2000 के 39.9 प्रतिशत से घटकर 2014 में 34.3 प्रतिशत और विकसित अमेरिका के लिए 2000 के 19.6 प्रतिशत से घटकर 13.1 प्रतिशत रह गया है. इसके अलावा, विकासशील एशिया नंबर एक वैश्विक निवेश गंतव्य स्थान बना हुआ है जिसका वैश्विक एफडीआई में लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा है. विकासशील एशिया में अंतर्वाह 2014 में लगभग आधे ट्रिलियन डॉलर के रेकॉर्ड स्तर पर (2000 में 159 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 465 बिलियन यूएस डॉलर) पहुंच गया. विकासशील एशिया में एफडीआई अंतर्वाह यूरोपीय संघ (258 बिलियन यूएस डॉलर) और उत्तर अमेरिका में विकसित अर्थव्यवस्थाओं (146 बिलियन यूएस डॉलर) से काफी अधिक रहा. एफडीआई बहिर्वाह क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है. विकासशील एशिया से एफडीआई का बहिर्वाह भी 2000 के 95 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 2014 में 432 बिलियन यूएस डॉलर के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

वैश्विक मांग में अनुमानित वृद्धि

उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समग्र आयात मांग विकासशील एशिया द्वारा संचालित होने का अनुमान है. विकासशील एशिया में आयात वृद्धि जोरदार बनी रहने का अनुमान है : 2014 में 6.2 प्रतिशत से 2020 में 7 प्रतिशत व्यापार में विकासशील एशिया की जोरदार वृद्धि बढ़ते अंत: एशियाई व्यापार द्वारा रेखांकित होती है. अंत: एशियाई निर्यात/आयात ने हाल के वर्षों में तीव्र वृद्धि दर्ज की है.

संभावनाएं तथा चुनौतियां

विकासशील एशिया द्वारा 2015-2020 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर से वृद्धि दर्ज किए जाने की उम्मीद है. निर्यात वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी द्वारा संचालित होगी. घरेलू मांग को क्षेत्र के भीतर स्वस्थ श्रम बाजार तथा जोरदार ऋण वृद्धि से समर्थन मिलेगा.

एशिया का भविष्य उज्ज्वल है और एशिया अपना वृद्धि मॉडल बदलने की राह पर है. मैकिन्से द्वारा किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि ऊर्जा, परिवहन, आवास, संचार तथा जल सुविधाओं में कमी से पिछले दशक के दौरान एशिया के जीडीपी में 3 से 4 प्रतिशत बिंदु तक आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुई है.

एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण के लिए अवसर

मैकिन्से के अनुसार, अगले दस वर्षों के दौरान उभरते एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 80 प्रतिशत से अधिक मांग उच्चतर आर्थिक कार्यकलाप को समर्थन देने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा तथा परिवहन से आएगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के संभाव्य समूह को व्यापक बनाने और पूंजी बाजार के विशाल वित्तीय संसाधनों का दोहन करने की आवश्यकता है. इसके लिए वित्तीय लिखतों का व्यापक संमिश्र आवश्यक है इस दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तथा बांड दोनों में भारी संभाव्यता है.

भारतीय एक्ज़िम बैंक: एशिया के विकास में भागीदार

एशियाई देश भारत सरकार के लिए हमेशा एक फोकस क्षेत्र रहे हैं और इस प्रकार यह देश दुतरफा व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा तथा समर्थन देने की बैंक की रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहे हैं.

एशिया में भारतीय एक्ज़िम बैंक की वित्तपोषण, सलाहकारी तथा सहायता सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एशिया में 10 देशों में 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की 34 प्रवर्तनशील ऋण व्यवस्थाएं
- भारतीय कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में फैली कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता
- संयुक्त उद्यमों के लिए सहायता
- एशिया के कई देशों में संस्था निर्माण प्रक्रिया में शामिल होकर अनुभवों को साझा करना
- अंकटाड के तत्वावधान में एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्जिड) का सृजन
- एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम का सृजन

सीएलएमवी में परियोजना विकास एवं सुगमीकरण फ्रेमवर्क (पीडीएफएफ)

- वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने 'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुसार सीएलएमवी क्षेत्र में भारतीय हितों का ध्यान रखने के लिए एक परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसका प्रबंध एक्ज़िम बैंक द्वारा किया जाएगा.
- 500 करोड़ रुपये के कुल कोष के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा 100 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है.
- पीडीएफ टीम सीएलएमवी क्षेत्र में अर्थक्षम परियोजनाओं की पहचान करेगी और भारतीय व्यापार तथा निवेश के सुगमीकरण के लिए पीडीएफ से प्रारंभिक सहायता के साथ एसपीवी के माध्यम से इन परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करेगी.

भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंधों में पिछले दशक के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. द्विपक्षीय व्यापार 2005 के 1.7 बिलियन यूएस डॉलर से नौ गुने से अधिक बढ़कर 2014 में 15.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया (तालिका). इस तेजी को ईरान - भारत के बीच व्यापार वृद्धि से समर्थन मिला है जिसमें ईरान से भारत का आयात भारत के निर्यात से अधिक रहा है. ईरान के साथ सामान्यत: भारत का व्यापार घाटा रहता है जो 2006 के 4.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2012 में 10.8 बिलियन यूएस डॉलर और फिर 2014 में घटकर 6.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया.

2014 के दौरान ईरान भारत का चौबीसवां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान था जिसका भारत के वैश्विक निर्यात में 1.4 प्रतिशत हिस्सा रहा. ईरान भारत के आयात का भी पन्द्रहवां सबसे बड़ा स्रोत था जिसका भारत के वैश्विक आयात में 2.4 प्रतिशत हिस्सा रहा. ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चैनल धीरे-धीरे बंद हो गए.

ईरान के साथ भारत का व्यापार

ईरान को भारत के निर्यात में चावल, मशीनरी एवं उपकरण, धातु, प्राथमिक तथा अर्द्ध-तैयार लौह एवं इस्पात, फार्मास्युटिकल्स तथा परिष्कृत रसायन, संसाधित खनिज, मानव निर्मित यार्न एवं फैब्रिक्स, चाय, कार्बनिक / अकार्बनिक / कृषि रसायन तथा रबड़ निर्मित उत्पाद आदि शामिल हैं.

ईरान से भारत के आयात में कच्चे तेल की प्रधानता है जिसका ईरान से भारत के कुल आयात में 85.9 प्रतिशत हिस्सा रहा; 2014 में भारत ईरान से कच्चे तेल के निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार था. दूसरी ओर, उसी वर्ष के दौरान ईरान भारत का कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था. ईरान से आयात सतत रूप से कम हुआ है क्योंकि यूएस तथा अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से भुगतान चैनल अवरुद्ध हो गए तथा शिपिंग मार्ग अस्त व्यस्त हो गए. फरवरी 2013 से, जब यूएस ने ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भुगतान चैनलों को अवरुद्ध कर दिया, भारत यूको बैंक के साथ एक व्यवस्था के माध्यम से ईरान के 45 प्रतिशत तेल बिल का भुगतान रुपये में कर रहा है.

ईरान के साथ भारत के निवेश संबंध

अप्रैल 1996 से सितंबर 2015 के दौरान, ईरान में संयुक्त उद्यमों तथा पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में संचयी अनुमोदित भारतीय एफडीआई (एफडीआई बहिर्वाह) 183.4 मिलियन यूएस डॉलर था. एस्सार, ओवीएल, टाटा स्टील, परसिया रोहित माइन्स एंड इंडस्ट्रीज कंपनी आदि जैसी कंपनियों की ईरान में मौजूदगी है. भारतीय स्टेट बैंक का तेहरान में प्रतिनिधि कार्यालय है.

अप्रैल 2000 से फरवरी 2015 के दौरान ईरान से भारत का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 0.6 मिलियन यूएस डॉलर रहा. भारत और ईरान के बीच संयुक्त उद्यमों में ईरानो-हिंद शिपिंग कंपनी, मद्रास फर्टीलाइजर कंपनी तथा चेन्नै रिफाइनरी शामिल हैं.

दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करार (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं.

चाबहार पोर्ट के लिए ईरान के साथ भारत का समझौता

2003 में भारत तथा ईरान के बीच चाबहार परियोजना को निष्पादित करने के लिए सहमति हुई थी, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इस उद्यम की प्रगति धीमी रही. अक्टूबर 2014 में भारत ने चाबहार पोर्ट में दो पूर्णत: निर्मित बर्थों को सुसज्जित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए एक अंतर सरकारी सहमति ज्ञापन (एमओयू) को अनुमोदित किया. ढांचे के अनुसार, एक भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी चाबहार पोर्ट के चरण-1 परियोजना में दो पूर्णत: निर्मित बर्थों को 10 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर देगी जिसका पारस्परिक सहमति से नवीकरण किया जाएगा. पोर्ट एक विशेष निधि (एसपीवी) के जरिए विकसित किया जाएगा जो बर्थों को कंटेनर टर्मिनल तथा बहु-उद्देश्य कार्गो टर्मिनल में परिवर्तित करने के लिए 85.21 मिलियन यूएस डॉलर निवेश करेगी. भारतीय पक्ष निवेश के माध्यम से प्राप्त उपकरणों का स्वामित्व दस वर्ष की समाप्ति पर किसी भुगतान के बिना ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (पीएंडएमओ) को सौंप देगा. कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तथा कांडला पोर्ट ट्रस्ट को शामिल करते हुए एक संयुक्त उद्यम या अन्य उपयुक्त एसपीवी गठित करने के लिए मंजूरी दे दी है. भारतीय संयुक्त उद्यम को समर्थन देने के लिए 22.95 मिलियन यूएस डॉलर के वार्षिक राजस्व खर्च के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है.

ईरानी सरकार द्वारा चाबहार को मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है. दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व तथा अफगानिस्तान में कारोबारी केन्द्रों के साथ जोड़ने के लिए इसे ईरान के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है.

तालिका: ईरान के साथ भारत का व्यापार 2005 – 2014 (बिलियन यूएस डॉलर)

मद	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ईरान को भारत का निर्यात	1.1	1.6	1.8	2.3	1.9	2.5	2.5	2.6	5.4	4.4
ईरान से भारत का आयात	0.6	5.9	9.2	13.8	10.6	11.1	11.5	13.3	10.0	11.2
ईरान के साथ भारत का कुल व्यापार	1.7	7.5	11.0	16.1	12.5	13.6	14.0	15.9	15.5	15.7
ईरान के साथ भारत का भुगतान संतुलन	0.4	-4.3	-7.3	-11.5	-8.6	-8.6	-9.0	-10.8	-4.6	-6.8

स्रोत : ट्रेड मैप , आईटीसी जिनेवा

06 मेक इन इंडिया : पहलें तथा परिणाम

'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम का उद्देश्य भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश प्राप्तकर्ता और विनिर्माण, डिजाइन तथा नवोन्मेष के लिए एक वैश्विक हब के रूप में विकसित करना है. इस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्तमान में कुल 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है. देश में कारोबार करने की सहूलियत में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं. इनमें अन्य के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेंस तथा औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, कंपनी अधिनियम में अनुकूल संशोधन, निर्यात तथा आयात के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में कमी और मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल बनाना शामिल है.

देश में निवेशों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं इनमें. डीआईपीपी वेबसाइट पर औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए एफएक्यूज प्रकाशित करना, रिटेल / एनआरआई / ईओयू विदेशी निवेशों से संबंधित मामलों में दाखिल आवेदनों पर कार्रवाई के लिए निश्चित समय-सीमा और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए निवेशक सहायता कक्ष शुरू करने संबंधी उपाय प्रमुख हैं.

इसके अलावा सरकार ने एफडीआई नीतियों का सरलीकरण भी किया है, जिनमें अन्य के साथ निम्न शामिल हैं:

- बैंकिंग तथा रक्षा से भिन्न सेक्टरों के लिए एफडीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) तथा पात्र विदेशी निवेशकों के लिए अलग-अलग उच्चतम सीमाओं को एकल सीमा से प्रतिस्थापित किया गया है.
- चिकित्सा साधनों, दूरसंचार क्षेत्र तथा एकल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है.
- बीमा तथा संबंधित कार्यकलापों में एफडीआई की उच्चतम सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की गई है.
- कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज तथा डिपॉजिटरी, पॉवर एक्सचेंज, पीएसयू द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन, कुरियर सेवा में एफडीआई को अब स्वत: मार्ग के अंतर्गत ला दिया गया है.
- रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत की एफडीआई सीमा को सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है. स्वत: मार्ग के अंतर्गत 24 प्रतिशत तक एफपीआई की अनुमति दी गई है. सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति के अनुमोदन से मामला-दर-मामला आधार पर 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई की भी अनुमति दी गई है.
- रेलवे की कुछ परियोजनाओं के निर्माण, परिचालन तथा रख-रखाव के लिए स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है.

सरकार औद्योगिक कॉरिडोर तथा स्मार्ट सिटी विकसित करने के साथ-साथ आधुनिकतम प्रौद्योगिकी तथा उच्च गति संचार के साथ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहती है. नवोन्मेषण तथा अनुसंधान कार्यकलापों को मजबूत रजिस्ट्रेशन प्रणाली और आईपीआर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी समर्थन दिया जाएगा.

कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 70 कौशल विकास योजनाएं 20 से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई हैं.

परिणाम

हालांकि संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम दिखाई देने में समय लगेगा किन्तु हाल के समय में कुछ सकारात्मक परिणाम नोट किए जा सकते हैं. सितंबर 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल के शुभारंभ के बाद अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह में पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

भारत में विदेशी पूंजी व्यय (कैपेक्स) अर्थव्यवस्था में अनुकूल वातावरण के फलस्वरूप बढ़ा है. 2015 की पहली तिमाही में प्राप्त 21.5 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कैपेक्स भारत द्वारा पिछले एक दशक के दौरान पहली तिमाही में प्राप्त अब तक का सर्वाधिक है. दूसरी तिमाही में भी, विदेशी कैपेक्स पिछले तीन वर्षों की तुलना में उच्चतर था (प्रदर्श).

इसके अलावा, निवेशक सुविधा सेवा केन्द्र अभियान की शुरुआत से उसके पोर्टल पर 12,000 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं. जापान, चीन, फ्रांस तथा दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने भारत में विभिन्न औद्योगिक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारी निवेश करने के अपने इरादे की घोषणा की है.

2015 के लिए विश्व बैंक की डुइंग बिजनेस रिपोर्ट में कई मानदंडों में भारत का प्रदर्शन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे

- **कारोबार शुरू करना:** रजिस्ट्रेशन शुल्क कम करने जैसे सकारात्मक कदमों के चलते इसमें सुधार हुआ. हालांकि इस मानदंड के अंतर्गत भारत के लिए समग्र अंक में सुधार हुआ किन्तु कारोबार शुरू करने के लिए रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में गिरावट आयी.
- **बिजली कनेक्शन:** नये कनेक्शन के लिए प्रतिभूति जमा में कमी से मुंबई में प्रभाव पडा जिससे इस अंक में सुधार हुआ. तथापि समग्र रैंक में फिसलन आयी.
- **अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण:** इस कार्य को बोर्ड के सदस्यों द्वारा अधिक प्रकटन, पार्टी लेन-देनों से संबंधित प्रतिकूल मामलों में उपलब्ध उपचारों में वृद्धि और निजी कंपनियों के शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों द्वारा मजबूत किया गया है. इस सूचकांक में, भारत का रैंक 2014 के 21 से सुधरकर 2015 में 7 पर आ गया.

विश्व बैंक की अगली रिपोर्ट में भारत की डुइंग बिजनेस रैंकिंग के निर्धारण में सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, विशेषकर उन श्रेणियों के अंतर्गत जिन्होंने दिल्ली तथा मुंबई में सुधार दर्ज किया है.

प्रदर्श : भारत में तिमाही विदेशी पूंजी व्यय (मिलियन यूएस डॉलर)

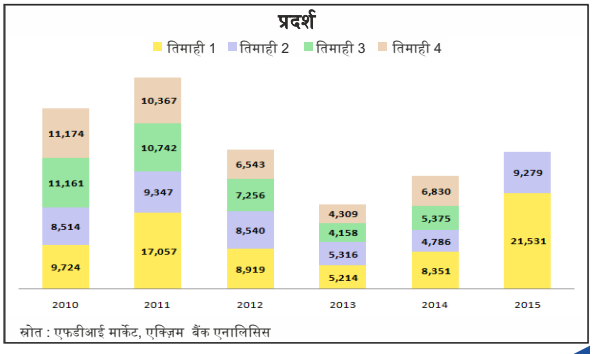

स्रोत : एफडीआई मार्केट, एक्ज़िम बैंक एनालिसिस

भारतीय एक्ज़िम बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझोले उद्यमों पर विशेष बल के साथ प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है.

एक्ज़िम बैंक की ऋण- व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम मुक्त, दायित्वरहित निर्यात वित्तपोषण विकल्प प्रदान करती हैं जिससे उन्हें विदेशों में नये बाजारों में प्रवेश करने और मौजूदा बाजारों में अपनी निर्यात मात्रा को बढ़ाने में सहायता मिलती है.

एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सरकारी और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना, परियोजना, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं.

एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. भारत सरकार के आदेश पर जारी ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल की शिपिंग पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अपफ्रंट करता है, बशर्ते कि संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत माल एवं सेवा भारत से लिया जाए.

ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत को उभरते बाजारों में परियोजना निष्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करने में भी समर्थ बनाया है. ऋण-व्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में विशेषकर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सीआईएस देशों में भारतीय परियोजनाओं का पर्याप्त गति पकड़ने में सहायता प्रदान की है.

बैंक की वर्तमान में 200 ऋण-व्यवस्थाएं परिचालन में हैं जिनके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप तथा सीआईएस के 63 देशों में 12.22 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण-व्यवस्थाएं भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं. इस प्रकार ऋण- व्यवस्थाएं भारत से विकासशील देशों को परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में कार्य करती हैं.

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश और सहयोग से जुलाई-सितंबर 2015 तिमाही के दौरान निम्नलिखित दो ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं :

- कोत दि'वार सरकार को कोत दि'वार एवं माली के बीच विद्युत इंटरकनेक्शन के वित्तपोषण के लिए 24 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था: उक्त ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के आदेश पर कोत दि'वार गणराज्य सरकार को अब तक कुल 136.30 मिलियन यू एस डॉलर की पाँच ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं. 26.80 मिलियन यू एस डॉलर की पहली ऋण-व्यवस्था अगस्त 2005 में अबिदजान में ग्रामीण परिवहन प्रणाली के नवीकरण तथा कृषि परियोजना के लिए प्रदान की गई थी. 25.50 मिलियन यू एस डॉलर की दूसरी ऋण-व्यवस्था जून 2008 में (i) महात्मा गांधी आई टी - बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क, (ii) मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्र तथा (iii) नारियल फाइबर प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी. 30 मिलियन यू एस डॉलर की तीसरी ऋण-व्यवस्था दिसम्बर 2009 में कोत दि'वार एवं माली के बीच ट्रांसमिशन लाईन परियोजना के वित्तपोषण के लिए लिए प्रदान की गई थी. 30 मिलियन यू एस डॉलर की चौथी ऋण-व्यवस्था मार्च 2010 में चावल उत्पादन कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी. कोत दि'वार गणराज्य एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसके पश्चिम में लाइबेरिया तथा गिनी, उत्तर में माली एवं बुर्किनाफासो, पूर्व में घाना तथा दक्षिण में गिनी की खाड़ी (अटलांटिक महासागर) स्थित हैं.
- गिनी गणराज्य सरकार को गिनी के कंकन तथा ज़ेरोकोर में क्षेत्रीय अस्पतालों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 35 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था: एक्ज़िम बैंक द्वारा गिनी गणराज्य सरकार को प्रदत्त यह पहली ऋण-व्यवस्था है. गिनी गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित है जिसके पश्चिम में उत्तरी एटलांटिक महासागर, उत्तरी सीमा पर गिनी बिसाऊ, सेनेगल तथा माली एवं दक्षिणी सीमा पर सियरा लिओन, लाइबेरिया एवं कोत दि'वार स्थित हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :
नदीम पंजेतन
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कपरेड,
मुंबई 400 005
फोन: (022) 22172310
फैक्स: (022) 22182460
ईमेल: eximloc@eximbankindia.in

वाणिज्य सचिव द्वारा 'सीएलएमवी के साथ आर्थिक एकीकरण हेतु भारत की रणनीति' पर रिपोर्ट का विमोचन

नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'सीएलएमवी के साथ आर्थिक एकीकरण हेतु भारत की रणनीति', भारत तथा कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) क्षेत्र के बीच वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहबद्धता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. भारत तथा सीएलएमवी के बीच आर्थिक सहयोग को मुमकिन बनाने वाले प्रमुख कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक निकटता, आर्थिक गतिशीलता और सीएलएमवी में सस्ती श्रम लागत शामिल हैं. वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेओतिया ने सितंबर 2015 की शुरुआत में नई दिल्ली में मंत्रालय की रिपोर्ट का विमोचन किया. मजबूत उत्पादन नेटवर्क और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) की मौजूदगी आसियान क्षेत्र की विशेषता है. हालांकि आरवीसी में भारत की सहभागिता कम रही है, आरवीसी शेष आसियान की तुलना में सीएलएमवी में भी अधिक विकसित नहीं हैं. भारत और सीएलएमवी के बीच व्यापार तथा एफडीआई दोनों में आर्थिक सहबद्धता के स्तर को मजबूत करने की आवश्यकता है. भारत-सीएलएमवी आर्थिक संबंधों के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियों में सूचना तथा संचार अंतराल, कौशल अनुपलब्धता, बैंकिंग बाधाएं और आरवीसी में लघु एवं मध्यम उद्यमों को एकीकृत करना शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार सीएलएमवी के आर्थिक विकास लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करना आवश्यक है. इससे चीन-आसियान मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत सीएलएमवी से निर्यात के माध्यम से चीनी बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इससे 100 बिलियन यूएस डॉलर का अतिरिक्त निर्यात संभव होगा जो बदले में चीन के साथ भारत के व्यापपार घाटे को पूरा कर सकता है.

भारत और बेलारूस ने 2018 तक 1 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा

नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारामन ने मिन्स्क, बेलारूस में 7 सितंबर, 2015 को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग पर भारत – बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के सातवें सत्र की सह-अध्यक्षता की. बेलारूसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री विताली मिखाइलोविच वोक, उद्योग मंत्री, बेलारूस सरकार द्वारा किया गया. मिन्स्क में भारत – बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देशों के बीच 400 मिलियन यूएस डॉलर का वर्तमान व्यापार स्तर काफी कम है. अत: वर्ष 2018 तक 1 बिलियन यूएस डॉलर का लक्ष्य तय किया गया. दोनों पक्षों ने फार्मास्युटिकल, खनन मशीनरी, ऊर्जा, उर्वरक तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन में सहयोग बढ़ाने की संभाव्यता को चिन्हित किया.

डब्ल्यू एम टी ओ में सेवा व्यापार में एलडीसी को भारत द्वारा अधिमानी दर्जा

नई दिल्ली: केन्द्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2015 में विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं के व्यापार में कम विकसित देशों (एलडीसी) को भारत द्वारा अधिमानी दर्जा देने की अधिसूचना को अनुमोदित किया. भारत निम्न के संबंध में सेवाओं के व्यापार में एलडीसी को अधिमानी दर्जा अधिसूचित करेगा: जीएटीएस (बाजार पहुंच) का अनुच्छेद XVI; तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण; और भारतीय व्यवसाय तथा रोजगार वीजा के लिए आवेदन करने वाले एलडीसी आवेदकों को वीजा शुल्क से छूट. यह अधिमान्यता भारत द्वारा अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष तक वैध रहेगी. भारत ने शुल्क मुक्त अधिमान्य प्रशुल्क (डीएफटीएफ) स्कीम के रूप में माल व्यापार के क्षेत्र में एलडीसी को काफी पहले ही छूट संबंधी प्रस्ताव किया है. इस प्रस्ताव से भारत को एलडीसी मुद्दों पर अपनी अग्रणी स्थिति बनाये रखने तथा मजबूत करने में सहायता मिलेगी. इसके अलावा, दोहा दौर के विकास दायरे को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि भारत सेवाओं के व्यापार में भी एलडीसी को उदार ऑफर दे. इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका में कई एलडीसी देश हैं जिनके साथ भारत विशेष संबंध रखता है. सेवाओं के व्यापार में एलडीसी देशों को तरजीही दर्जे से वीजा शुल्क की माफी पर 6.5 करोड़ रुपये वार्षिक तथा एलडीसी आवेदकों को प्रबंधन तथा तकनीकी परामर्शी कोर्स में प्रशिक्षण पर 2.5 से 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की लागत आयेगी. जहां तक जीएटीएस (बाजार पहुंच) के अनुच्छेद XVI के अंतर्गत ऑफर का संबंध है, इसमें कोई प्रत्यक्ष वित्तीय भार नहीं है.

एसडीएफ में भारत के पूंजी अंशदान को उसके आर्थिक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में उपयोग की अनुमति

नई दिल्ली: केन्द्रीय कैबिनेट ने सार्क विकास निधि (एसडीएफ) में भारत के अंशदान का सामाजिक उद्देश्य के लिए मौजूदा अनुमोदन के अलावा आर्थिक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. इस अनुमोदन से सीमा-पार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. ऐसी परियोजनाओं से अंत: सार्क व्यापार सहित सार्क क्षेत्र की वृद्धि संभाव्यता में सुधार लाने और क्षेत्र में समाज के उपेक्षित/गरीब वर्गों को सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी. इसमें भारत के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एसडीएफ में भारत के पूंजी अंशदान की पुनर्संरचना है. एसडीएफ की स्थापना लोगों की आजीविका में सुधार लाने तथा क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करने के लिए 2008 में की गई थी.

एक्ज़िम बैंक ने ब्राजीलियाई विकास बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ऊफा, रूस : भारतीय एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर तथा ब्राजीलियाई विकास बैंक (बी एन डी ई एस) के प्रेसिडेंट श्री लुसियानो कौसिनो द्वारा ऊफा, रूस में गुरूवार, 09 जुलाई, 2015 को ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग प्रक्रिया की वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित एक इतर बैठक में एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए. इस सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य ज्ञान, सूचना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान, कर्मचारियों में परियोजना विकास कौशल सहित क्षमता निर्माण, कार्यक्रमों का संयुक्त आयोजन, शोध एवं विकास, पारस्परिक लाभ की परियोजनाओं जिनमें अन्य देशों में परियोजनाएं जैसे पी पी पी परियोजनाएं शामिल हैं के लिए प्रभावी तथा स्थाई वित्तीय समाधान जुटाना तथा सहवित्तपोषण आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग संबंधों को मजबूत करना है. भारतीय एक्ज़िम बैंक तथा बी एन डी ई एस ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग प्रक्रिया के अंतर्गत विकास बैंक के नामित सदस्य हैं. ब्रिक्स राष्ट्रों के अन्य नामित विकास बैंक सदस्यों में स्टेट कोऑपरेशन बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर्स-वेनेशकोनोमबैंक, रूस; चाइना डेवलपमेंट बैंक कार्पोरेशन तथा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका हैं. बी एन डी ई एस तथा भारतीय एक्ज़िम बैंक ने ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग प्रक्रिया के अंतर्गत कई बहुपक्षीय सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए हैं. इन बहुपक्षीय करारों के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी इन करारों के अंतर्गत निर्धारित नीति निदेशों को आगे बढ़ाने हेतु द्विपक्षीय करारों में शामिल हो सकती है. इस अवसर पर बोलते हुए श्री माथुर ने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत दोनों संस्थाओं के बीच परियोजनाओं का संयुक्त वित्तपोषण किया जाएगा. इसके अलावा, इस द्विपक्षीय करार से संस्थागत क्षमताओं को मजबूती मिलने के साथ-साथ दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार तथा निवेश संबंधों में वृद्धि होगी.

एक्ज़िम बैंक द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन

मुंबई: एक्ज़िम बैंक में 1 सितंबर 2015 से 15 सितंबर 2015 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया. इस अवधि के दौरान स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं, संगीत संध्या सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्टाफ सदस्यों को अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित तथा प्रोत्साहित करना था. हिंदी पखवाड़े की शुरुआत सीएमडी के संदेश से हुई. हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए 16 सितंबर, 2015 को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली तथा माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के संदेश स्टाफ सदस्यों में परिचालित किए गए. प्रसिद्ध विज्ञापन गुरू श्री पीयूष पांडेय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेंद्र माथुर ने की. बैंक द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए. इस अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त करते हुए श्री माथुर ने बैंक के स्टाफ सदस्यों को उनके दैनंदिन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि हिन्दी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने तथा समूचे भारत की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनने में सक्षम है और इसीलिए इसे हमारे संविधान द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है. उन्होंने स्टाफ सदस्यों को अधिक से अधिक भाषाओं को सीखने हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भाषाएँ हमें विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को जानने एवं समझने में हमारी मदद करती हैं.श्री पीयूष पांडेय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जन सामान्य तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम हैं. उन्होंने मत व्यक्त किया कि हिंदी बहुत तेजी से फैल रही है और विभिन्न भाषाओं से शब्दों को उदारतापूर्वक स्वीकार कर रही है जिसे सिनेमा तथा विज्ञापन जगत में इस्तेमाल हो रहे शब्दों से देखा जा सकता है. अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को बताते हुए उन्होंने स्टाफ सदस्यों से अपील की कि अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी का प्रयोग करें और कठिन शब्दों का प्रयोग करने से बचें. उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करने पर जोर दिया.

नई दिल्ली में परियोजना निर्यात पर एक्ज़िम बैंक का सेमिनार

नई दिल्ली : एक्ज़िम बैंक ने विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात तथा भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजना निर्यातों में प्रभावी वृद्धि के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु नई दिल्ली में 'परियोजना निर्यात हितधारकों के लिए सेमिनार' का आयोजन किया. भारतीय निर्यात-आयात बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में एशिया तथा अफ्रीका में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए लगातर नवोन्मेषी वित्तपोषण कार्यक्रमों एवं उत्पादों के माध्यम से भारतीय परियोजना निर्यातों को गति देने हेतु एक्ज़िम बैंक के प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता बहुत महत्वपूर्ण होगी. सेमिनार में एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक, श्री देबाशिस मल्लिक के संचालन में एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई जिसमें श्री विजय कुमार चौहान, कार्यपालक निर्देशक, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल); श्री अजय माथुर, मुख्य कार्याधिकारी, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल); श्री अतुल कुमार रस्तोगी, कार्यपालक निदेशक, टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल); श्री टी. के. साहू, कार्यपालक निदेशक - इंटरनेशनल ट्रेड डिविजन, स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया (सेल) तथा श्री एस. के. खुराना, कार्यपालक निदेशक, आई एस जी ई सी हैवी इंजीनियरिंग लि. जैसे उद्योग जगत के प्रमुख वक्ताओं ने भारतीय परियोजना निर्यात क्षेत्र में चुनौतियों एवं उनसे निपटने के उपायों पर विशेष चर्चा के साथ भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया.

10 भारतीय चमड़ा उद्योग: संभावनाएं

चमड़ा तथा उसके उत्पाद अपनी शैली तथा फैशन के लिए विख्यात हैं. पर्यावरण चिंताओं तथा कच्चे माल की उपलब्धता और सस्ती श्रम लागत जैसे प्रतिस्पिर्धी लाभ ने चमड़ा क्षेत्र के प्रोसेसिंग सेगमेंट को विकासशील देशों की ओर मोड़ने में योगदान दिया है.

भारतीय चमड़ा उद्योग

भारतीय चमड़ा उद्योग परिवर्तन के बड़े दौर से गुजरा है. साठ तथा सत्तर के दशकों में यह सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक था किंतु आज तैयार, मूल्य योजित रबड़ उत्पादों का निर्यातक बन गया है. भारतीय चमड़ा उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी दोनों बाजारों में स्वयं को एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित कर लिया है.

चमड़ा उद्योग एक रोजगार गहन क्षेत्र है जिसमें लगभग 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है. चमड़ा क्षेत्र में चर्मशोधनशाला (जहां को खाल चमड़े में रूपांतरित किया जाता है) और विनिर्माण इकाइयां (जहां चमड़े के जूते, गार्मेंट तथा आउटवेयर और मिश्रित चमड़े के सामान तैयार किए जाते हैं) शामिल हैं. ये उत्पादन सुविधाएं मुख्यत: असंगठित (मुख्यत: पारिवारिक स्वामित्व) इकाइयों / उत्पादन केन्द्रों में फैली हैं जिनका कुल उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत योगदान होता है.

यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन करने की क्षमता के साथ प्रचुर मात्रा में कच्चा माल (विश्व पशु एवं भैंस उत्पादन का 18 प्रतिशत तथा विश्व भेंड़ व बकरी उत्पादन का 9.2 प्रतिशत), कुशल श्रमशक्ति और टेक्नोलॉजी है.

भारतीय चमड़ा निर्यात

भारत से चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2014-15 में 6494.4 मिलियन यूएस डॉलर रहा (तालिका). चमड़े के जूते 45 प्रतिशत हिस्से के साथ चमड़ा निर्यात के सबसे बड़े घटक हैं. चमड़े के अन्य उप-क्षेत्रों में चमड़े की वस्तुएं (22 प्रतिशत), तैयार चमड़ा (21 प्रतिशत), लेदर गार्मेंट (9 प्रतिशत) और घोड़े का साज-सामान व काठी (3 प्रतिशत) शामिल हैं.

चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों का निर्यात पिछले दो दशकों के दौरान कई गुना बढा है तथा यह 1990-91 में 1.42 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2010-11 में लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर तथा फिर 2014-15 में 6.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. यह उद्योग आज भारत में विदेशी मुद्रा अर्जक प्रमुख दस उद्योगों में शामिल है.

भारतीय चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के लिए मुख्य निर्यात बाजार (2014-15 में 12.3 प्रतिशत हिस्से के साथ) जर्मनी था. 2014-15 में अन्य प्रमुख बाजार थे – यूएसए (11.8 प्रतिशत), यूके (11.6 प्रतिशत), इटली (7.8 प्रतिशत), हांगकांग (6.5 प्रतिशत), फ्रांस (5.7 प्रतिशत), स्पेन (5.4 प्रतिशत) और नीदरलैंड (3.5 प्रतिशत). इन देशों का 2014-15 में भारत द्वारा चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के कुल निर्यात में दो-तिहाई से अधिक संयुक्त हिस्सा- रहा.

बाजार विविधीकरण के लिए संभावनाएं

भारतीय चमड़ा उद्योग मुख्यत: कुछ पारंपरिक बाजारों तक सीमित रहा है. हालांकि इन देशों में वित्तीय संकट के कारण उसे बाधाओं का भी सामना करना पड़ा है. उदाहरण के लिए, भारतीय जूते के शीर्ष 10 में से 8 बाजार यूरोप में हैं. यूरोप वर्तमान में धीमी जीडीपी वृद्धि और उपभोग में कमी से जूझ रहा है जिसका जूता उद्योग पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा.

हालांकि भारत घोड़े की काठी तथा साज-सामानों के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक है. किन्तु इस सेग्मेंट को लैटिन अमेरिका, रूस तथा मध्य पूर्व के बाजारों में दस्तक देने की आवश्यकता है.

इसके अलावा, कई उत्पाद श्रेणियों में, जहां भारत कुछ बाजारों के लिए प्रमुख आयात स्रोत है वही कई अन्य बाजारों में इसकी मौजूदगी नगण्य है. उदाहरण के लिए, जापान 2013 में चमड़े की बाहरी सतह वाले पॉकेट या हैंडबैग (एचएस: 420231) का सबसे बड़ा आयातक था किंतु इस बाजार में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.5 प्रतिशत था. इसके विपरीत, इन उत्पादों के लिए विश्व में भारत का हिस्सा 10.4 प्रतिशत था.

अपर्स तथा स्टीफनर्स के अलावा अन्य पार्ट्स के मामले में, (एचएस: 640610) वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा 10.9 प्रतिशत था, जबकि जापान के मामले में यह 2.0 प्रतिशत था. इंडो – जापान सीईपीए ने भारतीय चमड़ा उद्योग क्षेत्र के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए हैं तथा जापान ने कई मदों के लिए शुल्कों में रियायत प्रदान की है. चूंकि इनमें से कई उत्पाद बी 10 श्रेणी में हैं अत: आने वाले समय में बाजार पहुंच बढ़ने की उम्मीद है.

1. इस श्रेणी के अंतर्गत उत्पादों पर शुल्कों को आधार दर से 11 समान वार्षिक किस्तों में समाप्त कर दिया जाएगा. ऐसे माल 1 जनवरी 2021 से शुल्क मुक्त होंगे.

तालिका: भारत द्वारा चमड़े तथा चमड़ा उत्पापदों का निर्यात: हालिया रुझान (मिलियन यूएस डॉलर)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	% हिस्सास	सीएजीआर (%)
जूते (घटकों तथा गैर-चमड़ा सहित)	1758.7	2079.1	2066.9	2531.0	2945.2	45.3	13.8
चमड़े की वस्तुएं	855.8	1089.7	1180.8	1351.5	1453.3	22.4	14.2
तैयार चमड़ा	841.1	1024.7	1093.7	1284.6	1329.1	20.5	12.1
लेदर गार्मेंट्स	425.0	572.5	563.5	596.2	604.3	9.3	9.2
घोड़े का साज-सामान व काठी	87.9	3107.5	110.4	145.5	162.7	2.5	16.6
कुल	3968.7	4873.5	5015.4	5908.8	6494.4	100.0	13.1
स्रोत : चमड़ा निर्यात परिषद							

इस श्रेणी के उत्पादों पर ड्यूटी को 11 वार्षिक किस्तों में समाप्त कर दिया जाएगा. यह उत्पाद 1 जनवरी, 2021 से ड्यूटी फ्री होंगे.

अक्तूबर 2000 में 'भारत- रूस रणनीतिक भागीदारी घोषणा' पर हस्ताक्षर के साथ भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को गुणात्मक रूप से नया आयाम मिला है. कुल निर्यात-आयात दोनों में वृद्धि को दर्शाते हुए भारत और रूस के बीच कुल व्यापार 2005 के 3.1 बिलियन यूएस डॉलर से तिगुने से अधिक बढ़कर 2014 में 9.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया (तालिका). भारत को रूस का निर्यात 2005 के 2.3 बिलियन यूएस डॉलर से तीन गुना से अधिक बढ़कर 2014 में 6.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जबकि भारत से रूस का आयात लगभग चार गुना बढ़कर 2005 के 784 मिलियन यूएस डॉलर से 2014 में 3.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. रूस भारत के साथ सामान्यत: व्यापार अधिशेष रखता है जो 2005 के 1.5 बिलियन यूएस डॉलर से दुगुना होकर 2014 में 3.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया.

भारत को रूस के प्रमुख निर्यातों में मोती एवं बहुमूल्य रत्न (भारत को रूस के कुल निर्यात का 17.8 प्रतिशत), मशीनें एवं उपकरण (11.3 प्रतिशत), इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (7.6 प्रतिशत), उर्वरक (5.9 प्रतिशत) तथा ऑप्टिकल, फोटो एवं तकनीकी उपकरण (4.9 प्रतिशत) शामिल हैं.

भारत के लिए, रूस उर्वरकों के आयात का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक स्रोत, साल्ट, सल्फर, प्लास्टर तथा चूने के लिए चौथा सबसे बड़ा स्रोत, पेपर तथा पेपरबोर्ड का छठां सबसे बड़ा स्रोत, मोतियों बहुमूल्य रत्न और रबड़ एवं उसकी वस्तुओं के लिए नौवां सबसे बड़ा स्रोत और लौह एवं इस्पात के लिए दसवां सबसे बड़ा स्रोत है.

भारत से रूस के आयात समूह में फार्मास्युटिकल उत्पादों की प्रधानता है जिनका 2014 में रूस के वैश्विक आयात में 21.2 प्रतिशत हिस्सा रहा. भारत रूस द्वारा फार्मास्युटिकल के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और 2014 के दौरान उत्पाद के आयात के लिए पांचवां सबसे बड़ा स्रोत था. भारत के लिए, यूएसए तथा दक्षिण अफ्रीका के बाद रूस फार्मास्युटिकल के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान था. भारत से रूस के आयात समूह में अन्य के साथ साथ मशीनें एवं उपकरण, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अपॅरिल, मोती एवं बहुमूल्य रत्न और काफी तथा चाय शामिल हैं.

भारत - रूस व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए संभाव्यता

रूस के निर्यात बाजार के रूप में भारत की रैंकिंग में 2005 के 28 वें स्थान से 2014 में 18 वें स्थान पर रही है. साथ ही, रूस के ग्लोबल आयात में भारत की रैंकिंग 2005 के 26 वें स्थान से सुधरकर 23 वें स्थान पर आ गयी है.

द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और बढ़ाने तथा विशेषकर रूस के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे, जो पिछले दशक के दौरान दुगुना बढ़ गया है, को कम करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है. इसके लिए भारत की वैश्विक निर्यात क्षमता और रूस में विद्यमान मांग के अनुरूप रूस को भारतीय निर्यात की संभाव्य मदों की पहचान करने की जरूरत है. इससे रूस के आयात भागीदार के रूप में भारत की रैंकिंग बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी.

रूस के आयात समूह में प्रमुख मदों, हरेक उत्पाद क्षेत्र कोड में भारत का हिस्सा (2-अंकीय तथा 6 अंकीय एचएस कोड) और भारत की वैश्विक निर्यात क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भारत के न्यून हिस्से के आधार पर संभाव्य निर्यात मदों को चिन्हित करना प्रमुख रणनीति होगी.

उपर्युक्त मानदंड के आधार पर 2-अंकीय एचएस कमोडिटी वर्गीकरण के अनुसार रूस को निर्यात की संभाव्य मदों में निम्न लिखित शामिल होंगी :

- मशीनें एवं उपकरण (एचएस 84)
- इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (एचएस 85)
- रेलवे, ट्रामवे से इतर वाहन (एचएस-87)
- फार्मास्युटिकल उत्पाद (एचएस 30)
- प्लास्टिक तथा वस्तुएं (एचएस 39)
- ऑप्टिकल, फोटो तथा तकनीकी उपकरण (एचएस 90)
- लौह एवं इस्पात की वस्तुएं (एचएस 73)
- लौह एवं इस्पात (एचएस 72)
- मांस एवं खाद्य मांस ऑफल (एचएस 02)
- फर्नीचर, लाइटिंग, साइन (एचएस 94)
- ॲपरेल, एक्सेसरीज गैर बुनी या क्रोशेट (एचएस 62)
- जूते एवं गेटर्स (एचएस 64)
- खनिज ईंधन, तेल, आसवन उत्पाद (एचएस 27)
- विविध रासायनिक उत्पाद (एचएस 38)
- कार्बनिक रसायन (एचएस 29)
- मछली, क्रस्टेसन, सीप (एच एस 03)
- एल्युमिनियम एवं वस्तुएं (एचएस 76)
- खाद्य उद्योग अवशिष्ट, रद्दी

चार्ट: भारत के साथ रूस के व्यापार की प्रवृत्तियां, 2005-2014 (मिलियन यूएस डॉलर)

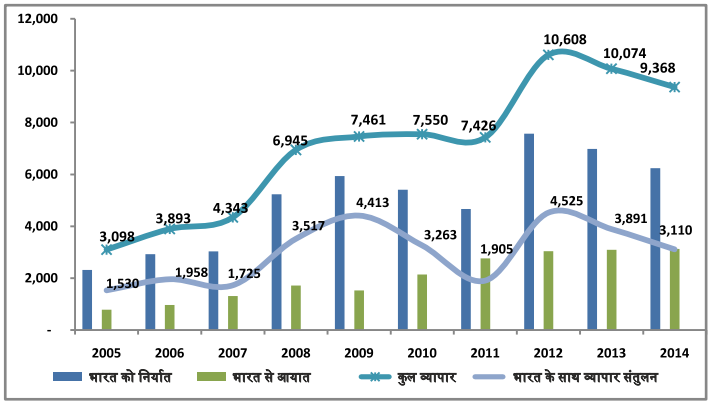

स्रोत : ट्रेड मैप, आईटीसी जिनेवा

एक्ज़िम बैंक के विपणन सलाहकारी कार्यकलाप
जुलाई-सितंबर 2015

भारतीय एक्ज़िम बैंक अपने विपणन सलाहकारी सेवाएं समूह के जरिए भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमताओं का सृजन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है. एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातक फर्मों की उनके उत्पादों एवं सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने हेतु वैश्विक स्तर पर विदेशी वितरकों/ क्रेताओं/ सहभागियों का पता लगाने में भी मदद करता है. संस्कृति का संरक्षण करने और भारतीय हस्तशिल्प एवं हैंडलूम क्षेत्र से पारंपरिक तथा अनूठी कला एवं शिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंक विभिन्न प्रदर्शनियों तथा कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए भी शिल्पकारों तथा कारीगरों की सहायता करता है.

इस संबंध में एक्ज़िम बैंक ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) के साथ मिलकर जयपुर, राजस्थान के पास के गांव अचरोल की ग्रामीण महिलाओं के लिए 14 से 28 सितंबर, 2015 के दौरान ब्लॉक प्रिंटिंग एवं डाइंग में एक डिजाइन इंटरवेंशन कार्यशाला का उद्घाटन किया.

अनूठी राजस्थान में ग्रामीण समुदायों में उपेक्षित तथा ग्रामीण महिलाओं को टेक्सटाइल में वैकल्पिक कॅरियर प्रदान करती है. अनूठी महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) है जो डिजाइन, शिल्प, सामुदायिक निर्माण तथा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक तथा वित्तीय सशक्तिकरण में मदद करता है. संस्था महिला शिल्पकारों को रिसाइकल किए गए फैब्रिक, हस्तनिर्मित कागज, पुराने सिल्क तथा कॉटन, लकड़ी, धातु, सिरैमिक, स्टोन्स तथा चांदी से घरेलू सजावटी सामान, उपहार वसतुएं, होम फर्नीशिंग, परिधान, बैग, आभूषण बनाने में प्रशिक्षित करती है.

इस कार्यशाला में एन आई डी की युवा एवं दक्ष डिजाइनरों द्वारा 20 से अधिक महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया. इस कार्यशाला का उद्देश्य नवोन्मेषी डिजाइनों पर उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है. इससे प्रतिभागियों को न केवल कई डिजाइनों को सीखने तथा ब्लॉक प्रिंटिंग एवं डाइंग में उनका उपयोग करने में मदद मिलेगी बल्कि उनमें डिजाइन कौशल का विकास होगा. इस कार्यशाला में प्रशिक्षित प्रतिभागी अपने समुदाय के अन्य शिल्पकारों को भी प्रशिक्षित कर सकेंगे. धीरे-धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग इन डिजाइनों को सीखकर उनका उपयोग कर सकेंगें. इस कार्यशाला से जयपुर के आसपास की ग्रामीण महिलाओं के जीविकोपार्जन तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी.

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रिंटिंग डिजाइनों को आधुनिक टच मिला. डाइंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, कान्था एम्ब्रायडरी तथा सिलाई से जुड़ी इन महिला प्रतिभागियों द्वारा रेडिमेड कपड़े तथा टेक्सटाइल, घरेलू एवं रसोई एवं बेड फर्निशिंग से संबंधित 20-25 तरह के प्रोटोटाइप उत्पाद तैयार किए गए.

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने महिला बुनकरों को ब्लॉक प्रिंटिंग तथा डाइंग की नई तकनीकें सीखने और उत्पाद विकास के संबंध में नवोन्मेषी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया.

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें:
सुश्री दीपाली अग्रवाल
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
मुंबई
फोन: (022) 22172829
ईमेल: mas@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

अमेज़िंग अफ्रीका – ए कॉरपोरेट जर्नी

लेखक एम डी रमेश तथा रणवीर चौहान

यह पुस्तक अफ्रीकी प्रांत में अनुभवों की यात्रा है जो अफ्रीकी प्रांत के बारे में जिज्ञासाओं का समाधान करने का कार्य करती है. पुस्तक में अफ्रीकी प्रांत में जीवन को काफी व्यापक और व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित किया गया है. एम डी रमेश तथा रणवीर चौहान अफ्रीकी प्रांत के साथ अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं. ओलम इंटरनेशनल टीम का एक हिस्सा होने के नाते दोनों लेखकों के पास उत्तरी घाना में शाकाहारी भोजन पाने में कठिनाइयों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने और मिस घाना प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाने तक प्रांत की कई रोचक कहानियां हैं.

अपने गहन अनुभवों के आधार पर लेखकों ने देश में कारोबारी माहौल, उनके फ्रैंकोफोन परिचालनों में कंट्रोल जनरल की भूमिका, दूर-दराज के क्षेत्रों में परिचालनरत कृषि-पण्य आपूर्ति श्रृंखला कारोबार के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, क्षेत्र में भर्ती की चुनौतियों और जिम्बाब्वे की प्रसिद्ध अति-मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों और रोचक कहानियों को साझा किया है.

पुस्तक में आंग्लोफोन तथा फ्रैंकोफोन देशों के बीच अंतर को उजागर करते हुए वृतांत भी दिए गए हैं जिसमें लेखकों का फ्रैंकोफोन की ओर प्रत्यक्ष झुकाव दिखाई देता है. अफ्रीकी प्रांत में स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र की स्थिति समझने के लिए भी इस पुस्तक को पढ़ना बनता है. लेखक की टिप्पणी है कि मृत्यु एक घटना है जिसे विश्व के अन्य भागों की तुलना में अफ्रीका में कम अशुभ माना जाता है और ऐसी घटनाओं में दु:ख प्रतीयमानत: संक्षिप्त होता है. यह ग्रामीण अफ्रीकी जीवन की स्थिति का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है.

केन्या

केन्या की अर्थव्यवस्था गत वर्ष में 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2014 में 5.3 प्रतिशत बढ़ी. कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सेवाएं तथा आईसीटी ने इस वृद्धि में योगदान दिया, जबकि निर्माण तथा पर्यटन क्षेत्र सामान्य रहे. स्थिर स्थूल आर्थिक परिदृश्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में सतत निवेश, उन्नत कारोबारी माहौल, निर्यात तथा क्षेत्रीय एकीकरण से 2015 में विकास की गति बनाये रखने में सहायता मिलने की उम्मीद है किंतु गरीबी तथा असमानता और साथ ही आंतरिक तथा बाह्य आघातों के प्रति अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता कीनियाई अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतिया हैं . तीव्र, सतत् वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए गरीबी, असमानता, अभिशासन, न्यून निवेश तथा न्यून उत्पादकता जैसी चुनौतियों का सामना करना देश के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं.

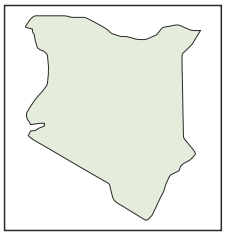

तुर्की

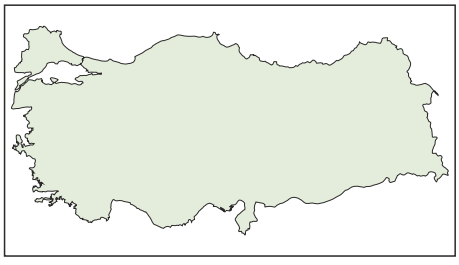

2014 में तुर्की की वृद्धि दर घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई क्योंकि निजी खपत तथा निवेश मामूली रहा. तुर्की को भारी मात्रा में बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता है जो लीरा को कमजोर कर रही है और चुनाव के बाद राजनैतिक पक्षाघात का अनुभव कर रही है. तथापि निजी खपत में 2014 के 1.4 प्रतिशत से 2015 में औसतन 2.7 प्रतिशत की सामान्य मजबूती की उम्मीद है जिससे आर्थिक वृद्धि में थोड़ी तेजी आएगी. तुर्की ने 'विजन 2023' के अंतर्गत 2023 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जीडीपी तथा 25000 यूएस डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने और बेरोजगारी में 5 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा है. तुर्की की अर्थव्यवस्था के 2015 तथा 2016 में 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का पूर्वानुमान है क्योंकि निजी खपत में तेजी आने का अनुमान है.

वेनेज्यूएला

सिकुड़ती अर्थव्यवस्था, बेलगाम मुद्रास्फीति और तेल की न्यून कीमतों से 2015 में वेनेज्यूएला में दशक के दौरान जीडीपी में सबसे अधिक संकुचन होने की संभावना है जो (-) 7.4 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित है. तेल का वेनेज्यूएला के निर्यात में लगभग 95 प्रतिशत और सार्वजनिक राजस्व में आधा हिस्सा रहता है किंतु तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट ने विदेशी मुद्रा आय को सीमित कर दिया है जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है तथा माल में भारी कमी हो रही है. वेनेज्यूएला ने बांड भुगतान के रूप में 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की राशि अदा करने तथा आयातों का निधीयन करने के लिए अपने स्वर्ण भंडार को बेचने का आश्रय लिया है. डांवाडोल विदेशी मुद्रा भंडार के चलते आगामी वर्षों में देश अपने ऋण दायित्वों को कैसे पूरा करेगा तथा अपने बाह्य असंतुलन का वित्तपोषण कैसे कर सकेगा यह एक प्रश्न चिन्ह है.

लाओपीडीआर

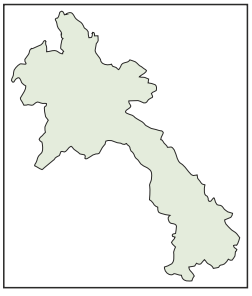

लाओ पीडीआर की अर्थव्यवस्था देशी मांग में तेजी तथा निर्माण, वानिकी और सेवाओं में उछाल की बदौलत 2014 में 7.5 प्रतिशत की तीव्र गति से बढ़ी. बिजली क्षेत्र में निवेश जोरदार रहने की उम्मीद है, जबकि समग्र जीडीपी वृद्धि दर खनन में उत्पादन में गिरावट, नई खानों में कार्य स्थगन तथा धातु की वैश्विक कीमतों में गिरावट के फलस्वरूप 2015 में मंद होकर लगभग 6.4 प्रतिशत रहने की उम्मीाद है. आईएमएफ के अनुसार, राजकोषीय विस्तार, क्षेत्रीय वृद्धि में तीव्र मंदी और व्यापार तथा पूंजी अंतर्वाह की खराब होती स्थिति अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख संकट हैं. इसके अलावा, बाह्य स्थिति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बाह्य आघातों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

म्यांमार

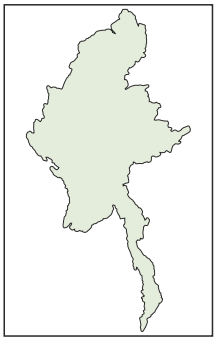

म्यांमार की अर्थव्यवस्था 2014-15 में वास्तविक रूप में 8.5 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन यह वृद्धि हालिया बाढ़ और घटते निवेशों के कारण 2015-16 में 6.5 के सामान्य स्तर पर रहने का अनुमान है. आर्थिक सुधारों ने चालू कारोबारी माहौल तथा सामाजिक-राजनैतिक चुनौतियों के बावजूद उपभोक्ता तथा निवेशक विश्वास को समर्थन दिया है. निवेश संबंधित आयात की तेजी से बढ़ती मांग के चलते चालू खाते का घाटा बढ़ गया है. यूएस डॉलर की सामान्य मजबूती के साथ इसने म्यांमार की विनिमय दर पर दबाव डाला है. निजी क्षेत्र को ऋण में तीव्र वृद्धि ने मौद्रिक विस्तार को गति दी है. सुधार के मोर्चे पर सतत प्रगति को देखते हुए मध्यकालिक आर्थिक वृद्धि संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं. मुख्य भूमि दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे बड़े देश के रूप में म्यांमार के पास क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, उपजाऊ भूमि, पर्याप्त अप्रयुक्त कृषि संभाव्यता और प्राकृतिक संसाधनों का विपुल भंडार है. चीन तथा भारत के कटान पर इसकी भौगोलिक स्थिति इसे क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण बनाती है. इसके साथ ही खनिज, प्राकृतिक गैस, तथा कृषि उपजों के एक मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका इसे और अच्छी स्थिति में रखती है.

जापानी येन (जेपीवाई)

बाजार को व्यापक रूप से अपेक्षा थी कि बैंक ऑफ जापान अपनी हालिया बैठक के माध्यम से मौद्रिक नीति में शिथिलता की घोषणा करेगा, लेकिन केन्द्रीय बैंक बोर्ड ने एक भूचालला दिया क्योंकि इसने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में 8 -1 के रूप में मतदान किया. इस समाचार ने तत्काल जापानी येन के उछाल (यूएसडी/जेपीवाई गिरावट) को उत्प्रेरित किया.

राष्ट्रीय सीपीआई मुद्रास्फीति आंकड़ों में हालिया निराशाओं ने बैंक ऑफ जापान की ओर से नई कार्रवाई की अड़चनों का बढ़ा दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि केन्द्रीय बैंक निकट भविष्य में क्यूई खरीद को बढ़ावा देने वाले किसी भी निर्णय के बारे में अधिक सतर्क रहेगा. कुरोडा और उनके साथी बोर्ड सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा की कीमतों में तीव्र गिरावट अवस्फीति के जोखिम को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे और कार्रवाई का जोखिम संभावित लाभ से अधिक भारी है.

इस प्रकार बैंक ऑफ जापान और यूएस फेडरल रिजर्व की ओर से निष्क्रियता यूएस डॉलर/ जेपीवाई दर को कुछ कठिन स्थिति में छोड़ती है. तथापि दोनों में एक मुख्य अंतर यह रह जाता है कि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना है, जबकि बैंक ऑफ जापान क्यूई खरीद को जारी रखेगा. अन्य सब कुछ सामान्य रहने पर यह यूएसडी / जापानी येन को सपोर्ट करेगा और उसे मुख्य समर्थन मूल्य के ऊपर रखेगा.

आगामी अमेरिकी आर्थिक आंकडों में निराशा स्थिति को और शीघ्र परिवर्तित कर सकती है. यूएस फेडरल रिज़र्व ने यह स्पष्ट किया कि वह अपनी दिसंबर बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने का निर्णय ले सकता है और इसने अधिकांश प्रमुख मुद्राओं की तुलना में यूएस डॉलर को मजबूती प्रदान किया. 30 सितंबर 2015 को यूएसडी/ जेपीवाई 119.84 पर उद्धृत हो रहा था.

ब्रिटिश पाउंड (जीबीपी)

ब्रिटिश पाउंड वैश्विक वित्तीय बाजार संकट और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा समय से पहले ब्याज दरों में वृद्धि की संभावनाओं के चलते यूएस डॉलर (यूएसडी) तथा यूरो के मुकाबले फिर से कमजोरी के दबाव में आ गया है. हालांकि यूएस फेडरल रिजर्व के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समानता इसे यूएस डॉलर के कुछ व्यापक रूप से मजबूत होने के जोखिम से बचायेगी किन्तु इसकी कम आक्रामक कड़ाई और चालू बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियां मध्यावधि के दौरान जीपीबी/ यूएसडी पर भार डालना जारी रखेंगी. बाजार जीबीपी/यूएसडी को 2015 में 1.51 की वर्षांत दर से 2016 में 1.52 के स्थिर ट्रेडिंग रेंज में समेकित होने की उम्मीद करता है.

कच्चे तेल की कीमतों में वापसी और हाल के महीनों में जीबीपी की मूल्यवृद्धि ने यूके की मुद्रास्फीति की संभावनाओं को कम कर दिया है. बाजार मुद्रास्फीति की दर के 2016 के प्रारंभ में 1 प्रतिशत तक बढ़ने से पूर्व इस वर्ष के उत्तरार्ध तक लगभग शून्यं तक बने रहने की उम्मीद करता है. उसके बाद मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे 2016 में 1.2 प्रतिशत और 2017 में 1.8 प्रतिशत की वर्षांत दर की ओर बढ़ने की संभावना है क्योंकि मूल मुद्रास्फीति खोए हुए आधार को पुन: प्राप्त कर लेगी. यह इस वर्ष ब्याज दरों को बढ़ाने के बारे में बैंक ऑफ इंग्लैंड की दुविधा दर्शाता है. तथापि 2016 के प्रारंभ में इस दुविधा के धूमिल पड़ जाने की आशा है जिससे बैंक ऑफ इंग्लैंड 2016 की पहली छमाही में किसी भी समय मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की शुरुआत कर सकेगा. 30 सितंबर, 2015 को जीबीपी/ यूएसडी 1.5127 पर उद्धृत हो रहा था.

स्विस फ्रैंक (सीएचएफ)

स्विस विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर तेजी की प्रवृत्ति चालू बाजार अपेक्षाओं को रेखांकित करती है कि स्विस नैशनल बैंक (एसएनबी) बाजार में आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करना जारी रखेगा. विनिर्माण पीएमआई के सितंबर में 50 की न्यूनतम सीमा से नीचे वापस आने और वार्षिक खुदरा बिक्री वृद्धि दर के नकारात्मक रहने से वृद्धि की संभावनाएं अंशत: मुद्रा की शक्ति द्वारा तय होंगी. यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) द्वारा अतिरिक्त लिक्विडिटी बाजार के झेलने की बढ़ती संभाव्यता एसएनबी की भावी स्थिति को और उलझनपूर्ण बनाती है.

वस्तुत: देशी मौद्रिक नीति पर बाह्य कारकों के प्रभाव को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जमा दरों में और कटौती होगी. एसएनबी ने कहा है कि -0.75 प्रतिशत अंतिम सीमा नहीं है, अतएव यह -1.25 प्रतिशत की ओर बढ़ने में नहीं हिचकेगा.

वैश्विक वृद्धि में सामान्य उछाल और अवस्फीतिकारी पण्य मूल्य प्रभावों में कमी एसएनबी पर दबाव को कम कर सकती हैं, लेकिन संभाव्य ईसीबी कार्रवाई के संबंध में अनुकूल स्थिति बनी हुई है. जोरदार देशी वृद्धि की अपेक्षाएं यूरो क्षेत्र की वास्तविक अंतिम मांग पर निर्भर करेंगी जो विशुद्ध मुद्रा मूल्यांकन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं. यूरो क्षेत्र में उछाल को घरेलू वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए इससे मध्यावधि यूरो सीएचएफ सपोर्ट बना रहेगा.

30 सितंबर, 2015 को यूएसडी/सीएचएफ 0.9727 पर उद्धृत हो रहा था.

भारतीय निर्यात – आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण में शोध के लिए 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार की स्थापना की गई थी. इस पुरस्कार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में शोध को बढ़ावा देना है. यह पुरस्कार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती (1889-1989) के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था .

पुरस्कार हेतु उपर्युक्त क्षेत्रों में डॉक्टरेट उपाधि हेतु शोध कार्य करने वाले आवेदकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं . इन प्रविष्टियो में से उच्च प्रतिष्ठित स्वतंत्र ज्यूरी द्वारा पुरस्कार विजेता प्रविष्टि का चयन किया जाता है. पुरस्कार के विवरण भारत में तथा विदेशों में समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और जर्नलों में विज्ञापनों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं इन्हें भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में भी परिचालित किया जाता है . पुरस्कार में तीन लाख पचास हजार भारतीय रुपये की पुरस्कार राशि और प्रमाणपत्र शामिल है.

पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां

अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण पर भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों या समकक्ष शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा शोध कार्य (डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त या डॉक्टरेट उपाधि के लिए स्वीकृत) इस पुरस्कार की पात्रता के लिए पूर्व-आवश्यकता है. प्रस्तुतीकरण की मौलिकता तथा स्पष्टता को क्रेडिट दिया जाता है. शोध कार्य में भारत/ एक्ज़िम बैंक से संबंधित मुद्दों जैसे, विदेशी व्यापार , प्रत्यक्ष विदेशी व्यापार, संयुक्त उद्यम, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, व्यापार एवं निवेश को प्रभावित करने वाली नीतियां, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियां आदि प्रमुख विषय हो सकते हैं. पुरस्कार भारतीय रुपये में पुरस्कार पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा. एक्ज़िम बैंक द्वारा उन्हीं शोध प्रबंधों को प्रविष्टि के रूप में स्वीकार किया जाएगा जिन पर पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के चार पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्षों के दौरान और चालू कैलेंडर वर्ष के 30 सितंबर तक डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई हो अथवा उन्हें डाक्टरेट उपाधि के लिए स्वीकार किया गया हो. शोध प्रबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकता है तथापि यदि शोध प्रबंध हिंदी में है तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद देना जरूरी होगा.

पिछले 26 वर्षों (1989-2014) में 34 शोध प्रबंधों को ईरा पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसमें से चुने गए 23 शोध प्रबंध विदेशी विश्वविद्यालयों में किए गए थे.

अपनी स्थापना से ही यह पुरस्कार प्रसिद्ध रहा है और कई शोधकर्ताओं को उनके उच्च कोटि के शोध के लिए प्रदान किया गया है. पुरस्कार विजेता शोध प्रबंधों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विनिमय दर व्यवस्था, विकासशील देशों के बाह्य ऋण, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम, विदेश व्यापार व्यवस्था तथा रणनीतिक व्यापार नीति में शोध शामिल हैं. पुरस्कार विजेता डॉक्टोरल शोध प्रबंधों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के शोध शामिल हैं.

इस पुरस्कार के कुछ प्रमुख पिछले विजेता रहे हैं – डॉ. नागेश कुमार, डॉ. तरूण कबिराज, डॉ. ए. प्रसाद, डॉ. रजत आचार्य, डॉ. आदित्य भट्टाचार्य, डॉ. अवधूत नाडकर्णी, डॉ. पूनम गुप्ता, डा. साजिद चिनॉय , डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. देब कुसुम दास, डॉ. रश्मि बांगा, डॉ. प्राची मिश्रा तथा डॉ. देबाशीष मंडल. इन तमाम वर्षों में शिक्षा जगत में इस पुरस्कार को मिली ख्याति इस तथ्य से स्पष्ट है कि पुरस्कार के कुछ पिछले विजेताओं में आज के प्रमुख अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और शिक्षाविद् शामिल हैं.

2014 के लिए ईरा पुरस्कार का परिणाम

एक्ज़िम बैंक के ईरा 2014 पुरस्कार की घोषणा 27 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर द्वारा की गई. डॉ. वी. कल्याण शंकर को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कार (ईरा) 2014 का विजेता घोषित किया गया. डॉ. शंकर को यह पुरस्कार उनके शोध प्रबंध "चुर्निंदा दक्षिणपूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में चयनित पण्य विनिर्माणों के व्यापार में अंतर-देशीय मूल्य योजन श्रृंखलाओं का विश्लेषण" के लिए प्रदान किया गया है. भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविन्द सुब्रमणियन ने डॉ. वी. कल्याण शंकर को पुरस्कार के रूप में तीन लाख पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया तथा डॉ. वी. कल्याण शंकर के पुरस्कृत शोध प्रबंध पर आधारित एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख का विमोचन भी किया.

ईरा पुरस्कार के बारे में जानकारी देते हुए श्री माथुर ने बताया कि इस पुरस्कार का आरंभ 1989 में किया गया था और यह इस पुरस्कार का सत्ताईसवां वर्ष है. यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकास तथा संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को उनके द्वारा भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों में किए गए शोध प्रबंधों के लिए प्रदान किया जाता है. पुरस्कृत शोध प्रबंध पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री माथुर ने कहा कि इस शोध अध्ययन में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों के व्यापार में मूल्य योजना श्रृंखलाओं में होने वाले रोचक परिवर्तनों की विवेचना की गई है.

डॉ. कल्याण शंकर ने पुणे विश्वविद्यालय से वर्ष 2011 में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की. यह शोध प्रबंध डॉ. रोहिणी साहनी के मार्गदर्शन में लिखा गया है. वर्तमान में डॉ. कल्याण शंकर पुणे विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में आई सी एस एस आर पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के पद पर कार्यरत हैं.

एक्ज़िम बैंक का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कार (ईरा) अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा विकास व संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध एवं विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता है. बैंक द्वारा वर्ष 2015 के लिए पुरस्कार हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2015 है.

संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	**1708.5**	**1843.2**	**1835.8**	**1875.9**	**2050.6**	**2187.7[f]**
प्रतिव्यक्ति जीडीपी (यूएस डॉलर)	**1411.7**	**1498.5**	**1468.4**	**1476.4**	**1587.9[e]**	-
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	**8.9**	**6.7**	**5.1****	**6.9****	**7.4[P]****	**7.6[@]**
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	8.6	5	-0.2**	3.7**	0.2[P]**	1.9 (अप्रैल-जून)[P]**
उद्योग	7.6	7.8	2.9**	4.5**	6.1[P]**	6.5 (अप्रैल-जून)[P]**
सेवाएं	9.7	6.6	8.7**	9.1**	10.2[P]**	8.9 (अप्रैल-जून)[P]**
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)						
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	14.6	18.9**	17.7**	17.2**	16.1[P]**	14.2 (अप्रैल-जून)[P]**
उद्योग	27.9	32.9**	32.3**	31.7**	31.4[P]**	32.1 (अप्रैल-जून)[P]**
सेवाएं	57.5	48.2 **	50.0**	51.1**	52.5[P]**	53.7 (अप्रैल-जून)[P]**
जनसंख्या (मिलियन)	**1210.2**	**1230**	**1250.2**	**1270.6**	**1291.4[e]**	-
मुद्रास्फीति की दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	10.8	10.3	10.2	9.5	6.4	3.66 (अगस्त '15)
मुद्रास्फीति की दर (डब्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	9.6	8.9	7.4	6	2	-4.95 (अगस्त '15)
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	**4.8**	**5.8**	**4.9**	**4.4**	**4.1[e]**	**3.9[e]**
विनिमय दर (रु. / यूएस डॉलर, औसत)	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	66.08 (सितंबर 28,'15)
विनिमय दर (रु. / यूरो, औसत)	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	73.81 (सितंबर 28,'15)
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**249.8**	**306**	**300.4**	**314.4**	**309.6**	**111.6 (अप्रैल-अगस्त '15)**
% परिवर्तन	39.8	22.5	-1.8	4.7	-1.5	-15.8^
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	36.4	56.7	60.9	63.2	56.7	14.4 (अप्रैल-अगस्त '15)
% परिवर्तन	29	55.9	7.3	3.8	-10.2	-47.7^
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**213.4**	**249.2**	**239.5**	**251.2**	**252.8**	**97.2 (अप्रैल-अगस्त '15)**
% परिवर्तन	41.8	16.8	-3.9	4.9	0.6	-7.4^
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**369.8**	**489.3**	**490.7**	**450.2**	**447.5**	**168.8 (अप्रैल-अगस्त '15)**
% परिवर्तन	28.2	32.3	0.3	-8.3	-0.6	-11.5^
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	106	155	164	164.8	138.3	41.5 (अप्रैल-अगस्त '15)
% परिवर्तन	21.6	46.2	5.9	0.4	-16	-38.8^
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**263.8**	**334.3**	**326.7**	**285.4**	**309.3**	**127.3 (अप्रैल-अगस्त '15)**
% परिवर्तन	31.1	26.7	-2.3	-12.6	8.4	3.5^
व्यापार संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	**-120**	**-183.3**	**-190.3**	**-135.8**	**-138**	**-57.2 (अप्रैल-अगस्त '15)**
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)*	**124.6**	**140.9**	**145.7**	**151.5**	**155.4**	**51.1 (अप्रैल-जुलाई '15)**
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)*	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	18.3 (अप्रैल-जून '15)
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)*	**80.6**	**76.9**	**80.8**	**78.5**	**79.8**	**28.6 (अप्रैल-जुलाई '15)**
सेवा शेष (बिलियन यूएस डॉलर)*	44	64	64.9	73	75.6	22.5 (अप्रैल-जुलाई '15)
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)*	**-47.9**	**-78.2**	**-87.8**	**-32.4**	**-27.5**	**-6.2 (अप्रैल-जून '15)**
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3	-1.2 (अप्रैल-जून '15)
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	**304.8**	**294.4**	**292**	**304.2**	**341.6**	**352.0 (सितंबर 18,'15)**
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	**317.9**	**360.8**	**409.4**	**446.3**	**474.4**	-
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	18.2	20.9	22.3	23.6	23.7	-
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	65	78.2	96.7	91.7	84.7	-
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	20.4	21.7	23.6	20.5	17.9	-
कुल ऋण चुकौती अनुपात (%)	4.4	6	5.9	5.9	7.5	-
एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	**36**	**46.6**	**34.3**	**36**	**44.3**	**15.3 (अप्रैल-जुलाई '15)**
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	2	0.6	0.2	0.02	-	1.5 (अप्रैल-जुलाई '15)
एफआईआई (निवल) (बिलियन यूएस डॉलर)	29.4	16.8	27.6	5	40.9	-2.3 (अप्रैल-जुलाई '15)
एफडीआई बहिर्वाह (बिलियन यूएस डॉलर)	**17.2**	**10.9**	**7.1**	**9.2**	**1.7**	**0.8 (अप्रैल-जुलाई '15)**
मेमो मदें :	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015[f]**	**2016[f]**
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	**4.1**	**3.4**	**3.4**	**3.4**	**3.3**	**3.8**
उन्नवत अर्थव्यवस्थाएं	1.7	1.2	1.4	1.8	2.1	2.4
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	6.2	5.2	5	4.6	4.2	4.7
विश्व पण्य व्यापार (परिमाण, % परिवर्तन)	**6.9**	**2.5**	**3.1**	**3**	**3.5**	**4.7**
विश्व पण्य निर्यात (ट्रिलियन यूएस डॉलर)	**18**	**18.2**	**18.6**	**18.8**	**17.3**	**18.4**
विश्व पण्य निर्यात के मूल्य में वृद्धि (%)	**20**	**1**	**2.3**	**1**	**-8.1**	**6.5**

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक : केन्द्री य बजट, भारतीय रिजर्व बैंक मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट एवं साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, वित्त मंत्रालय, सीएसओ, ईआईयू, नैस्कॉम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ), डब्यूआईय ईओ, आईएमएफ.

टिप्पणीय: - भारत सरकार के अनुमान, पी – भारत सरकार के अग्रिम अनुमान, एफ – आईआईएफ पूर्वानुमान, - उपलब्ध नहीं, * - बजट 2015-16 अनुमान, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2015-16 में 8 से 8.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान, ** संशोधित आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार आंकड़े, *** 2009-10 से आंकड़े आईएमएफ भुगतान संतुलन मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर भुगतान संतुलन के आंकड़ों के मानक प्रस्तु तीकरण के नये फॉर्मेट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए हैं. @ आईआईएफ अनुमान, ^ % परिवर्तन गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में है.

चार्ट 1 : भारत का निर्यात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

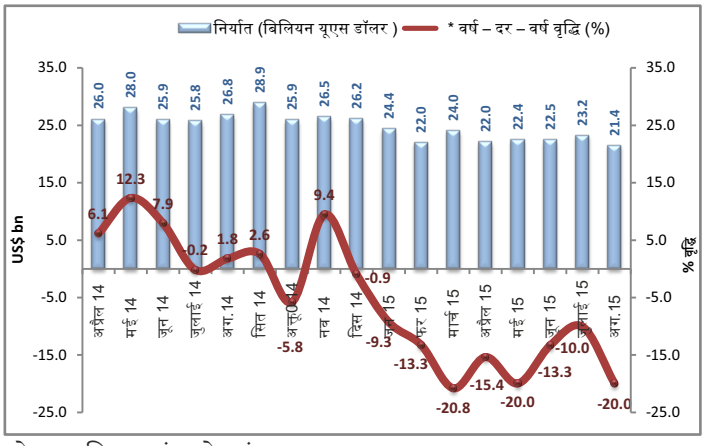

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 2 : भारत का आयात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

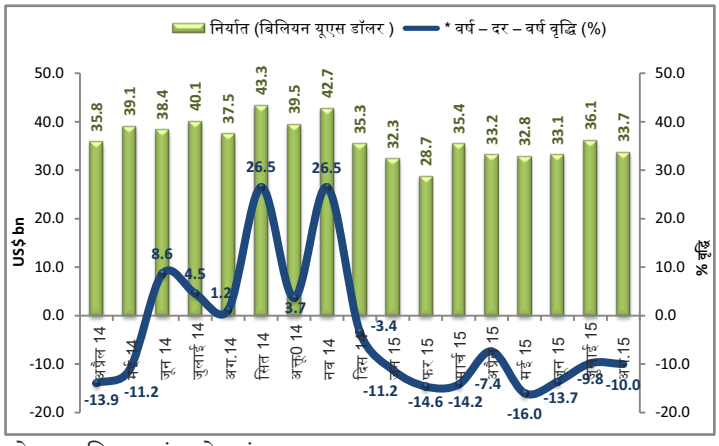

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 3 : 2015-16 में भारत की निर्यात संरचना (अप्रैल-जून)

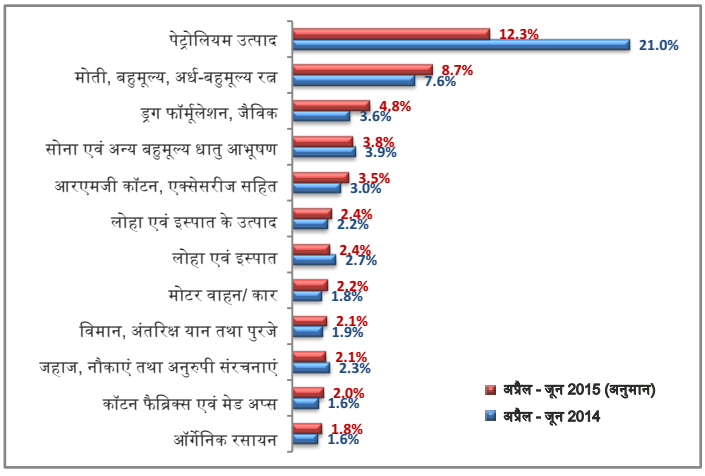

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 4 : 2015-16 में भारत की आयात संरचना (अप्रैल-जून)

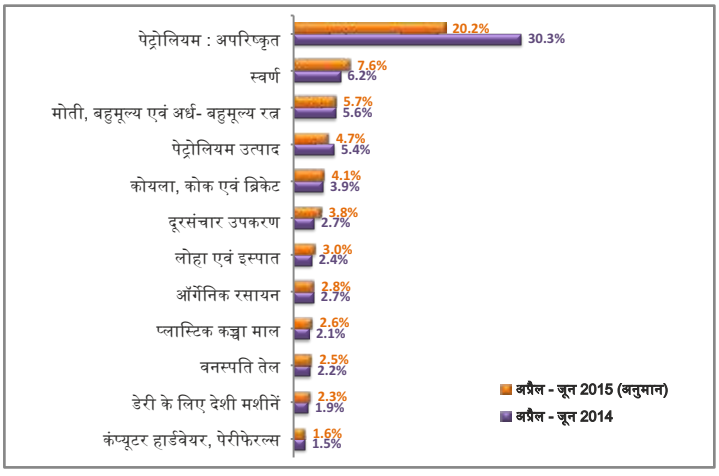

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 5 : विश्व पण्य निर्यात में भारत का हिस्सा

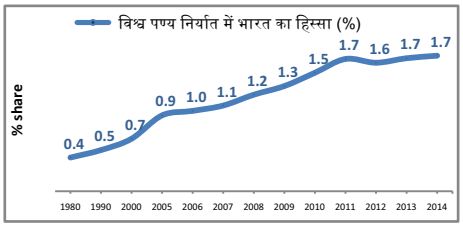

टिप्पणियां : 1) चीन 2009 में जर्मनी को प्रतिस्थापित करते हुए अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में उभरा. 2) भारत 2014 में 19 वां सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक बनकर उभरा है जो 2013 के 20 वें, 2007 के 26 वें और 2000 के 32 वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (30 सितंबर 2015को आकलित स्थिति)

चार्ट 6 : विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा

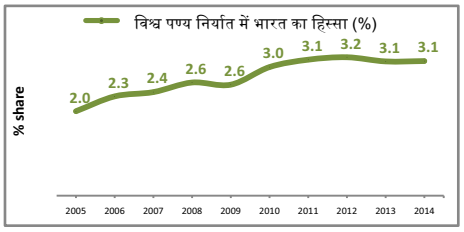

टिप्पणियां: 1) भारत वर्ष 2014 में छठां सबसे बड़ा वैश्विक सेवा निर्यातक बनकर उभरा है जो 2009 के 9 वें और 2005 के 11 वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (30 सितंबर 2015 को आकलित स्थिति)

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्रोतों/ माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रमाणिक हैं. प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रमाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है.

नोट: भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है.
1 करोड़: 10 मिलियन
1 लाख: 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई- 400 005
दूरभाष: +91-22-2217 2600
फैक्स: +91-22-2218 2572
ई-मेल: ccg@eximbankindia.in
वेबसाइट: www.eximbankindia.in

व्यापार एवं साझेदारी अवसर

व्यापार अवसर

हाथ से बुने कपड़े

अल्मोड़ा उत्तराखंड के 32 गांवों की 1500 महिला कारीगरों के साथ काम करनेवाली महिलाओं की बुनकर सोसाइटी. यह सोसाइटी हिमालय की प्राचीन हस्तशिल्प कलाओं पर आधारित हाथ से बुने और सिले कपड़े तैयार करती है.

बर्फ बनाने की मशीन

एक विनिर्माता जो बर्फ (आइस) बनाने की मशीन निर्माण करता है. यह मशीन विभिन्न उद्योगों जैसे होटेल्स, समुद्री खाद्य प्रोसेसिंग, रसायन तथा डाई उत्पादक उद्योगों के लिए उपयुक्त है.

वाटर पंप तथा मोटर

एक आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी जो स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी है, सबमर्सिबल स्टेनलेस स्टील पम्प तथा मोटर बनाती है. कंपनी विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त पंपिंग सॉल्यूशन तैयार करती है.

पॉली प्रोपिलीन मैट

हर तरह के उपयोग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीयुक्त विभिन्न प्रकार के डिजाइनों वाले फ्लोर मैट्स (चटाइयां) तैयार करने वाली कंपनी. आधुनिक डिजाइन वाले यह कार्पेट धुले जा सकते हैं (वाशेबल) हैं तथा इनका रख-रखाव बहुत ही आसान है.

रबड़ मोल्डेड कंपोनेंट

ऑटोमोटिव उद्योग में अनुप्रयोग के लिए कस्टम मेड रबड़ मोल्डेड कंपोनेंट एवं पार्ट्स के प्रमुख विनिर्माता.

मीटरिंग सॉल्यूशन

एक आई एस ओ 9001:14001 प्रमाणित कंपनी जो विद्युत क्षेत्र के विभिन्न व्यवसाय वर्टिकलों में है तथा ऊर्जा क्षेत्र को उच्च नवोन्मेषी एवं स्थायी सॉल्यूशन प्रदान करता है. ये वर्टिकल हैं- मीटरिंग सॉल्यूशन, पॉवर बैकअप एवं सोलर सॉल्यूशन तथा इंजीनियरिंग निर्माण एवं टनर्की संविदा आदि.

साझेदारी के अवसर

निवेश के अवसर

(i) मोजाम्बिक की एक कंपनी ई पी सी के लिए कच्चे माल जैसे नाइट्रीक एसिड तथा उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, एन पी के एवं डी ए पी के उत्पादन के लिए औद्योगिक उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए तकनीक आपूर्तिकर्ता और/ अथवा संभाव्यता ईक्विटी निवेशक के रूप में इच्छुक भारतीय कंपनियों की तलाश में है.

(ii) म्यांमार की एक कंपनी म्यांमार में सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सुविधा की स्थापना के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम साझेदार की तलाश कर रही है.

निर्यात के अवसर

- ईजिप्ट के आयातक को भारत से अलग-अलग आकार में कटे हुए प्री-पेंटेड गालवेनाइज्ड स्टील कॉयल चाहिए.
- यू एस की एक ई-कॉमर्स कंपनी को करूर, तमिल नाडु से हथकरघे से तैयार किए गए गृह सज्जा उत्पादों को आयात करने की इच्छुक है.
- रूस की फुटकर सुपरमार्केट को ताजे प्याज एवं आलू जैसे उत्पादों की आवश्यकता है.

इच्छुक पार्टियां नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर विपणन सलाहकारी सेवाएं समूह से संपर्क कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें- फोनः 2217 2600 एक्सटेंशनः 2707. फैक्सः 2218 8268 ई-मेलः mas@eximbankindia.in